

The House reassembled at two of the clock,
THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : The House stands adjourned to meet at 3.00 p.m.

The House then adjourned at one minute past two of the clock.

The House reassembled at three of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

GOVERNMENT BILL

The Constitution (One Hundred and Eighth Amendment) Bill, 2008

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we resume the consideration of the Constitution Amendment Bill...(Interruptions)... I call on the first speaker...(Interruptions)... I call on the first speaker, the Leader of the Opposition...(Interruptions)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Chairman, Sir...(Interruptions)...

श्री सभापति: आप लोग चुप हो जाइए और अपनी जगह वापस जाइए ...(व्यवधान)... आप लोग अपनी जगह वापस जाइए ...(व्यवधान)... राजनीति जी, प्लीज़ आप अपनी जगह जाइए ...(व्यवधान)... आप अपनी सीटों पर वापस जाइए, प्लीज़ ...(व्यवधान)... अपनी बात कहने का बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी जगह वापस जाइए ...(व्यवधान)... मैं आपसे कह रहा हूँ ...(व्यवधान)... राजनीति जी, प्लीज़ अपनी जगह वापस जाइए ...(व्यवधान)... Please, go back. ...(Interruptions)... आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं ...(व्यवधान)... प्लीज़, आप अपनी जगह वापस जाइए ...(व्यवधान)... राजनीति जी, साहू जी, प्लीज़, आप लोग अपनी जगह वापस जाइए ...(व्यवधान)... प्लीज़, कमाल अख्तर साहब, डॉक्टर साहब, आपके लिए यह करना मोहज़िब नहीं है, आप अपनी सीट पर जाइए ...(व्यवधान)... खान साहब, प्लीज़, आप अपनी जगह वापस जाइए ...(व्यवधान)... डॉक्टर साहब, प्लीज़, आप वापस जाइए ...(व्यवधान)... आप वापिस जाइए! ...(व्यवधान)... आप जाइए प्लीज़! ...(व्यवधान)... प्लीज़, आप जाइए! ...(व्यवधान)... आप लोग अपनी जगह चले जाइए, डिबेट शुरु होने वाली है। ...(व्यवधान)... कृपया आप लोग बैठ जाइए(व्यवधान)... कृपया आप लोग अपनी जगह पर चले जाइए ...(व्यवधान)...कृपया आप लोग अपनी जगह पर वापस जाइए ...(व्यवधान)... I shall now put the motion to vote. ...(Interruptions)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्र (उत्तर प्रदेश): महोदय, आप इसको बिना बहस के कैसे कर सकते हैं? ..(व्यवधान).. हम लोग बहस करने के लिए बैठे हुए हैं ...(व्यवधान)...

श्री एम. वेंकैया नायडु (कर्नाटक): सर, यह कोई तरीका नहीं है। सर, ऐसा पहली बार हो रहा है।..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.”

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, hon. Leader of the Opposition wants to start the debate...*(Interruptions)*... Please sit down ...*(Interruptions)*... Hon. Leader of the Opposition wants to speak on this...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The Leader of the Opposition will speak...*(Interruptions)*... Please ...*(Interruptions)*... The Leader of the Opposition wants to speak...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: सर, हम कैसे बैठ जाएं ? सर, हमारी सीट के नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं ? ...*(व्यवधान)*... अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम बाहर चले जाएंगे। ...*(व्यवधान)*...

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): यह बिल दलित महिलाओं के खिलाफ आ रहा है। पहले इस पर डिबेट होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए।

श्री अरुण जेटली: सर, इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करते वक्त ...*(व्यवधान)*... जिस उत्साह के साथ ...*(व्यवधान)*...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, I want to speak. I am sitting here. Now, I cannot sit here. यहां पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। यहां पर बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप हाउस को आर्डर में लीजिए। ...*(व्यवधान)*... I want to sit in my seat...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let the Leader of the Opposition speak ...*(Interruptions)*... Please...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Where should I sit? ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप अगली सीट पर बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: सर, पहले हाउस में व्यवस्था करवा लीजिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: वह हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: सर, यहां पर बैठने की जगह नहीं है, कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, कैसे हम अपनी सीट पर बैठेंगे, कैसे हम पार्टिशिपेट करेंगे? पहले आप हाउस को आर्डर में करिए। ...*(व्यवधान)*... Where should I sit, Sir? ...*(Interruptions)*... Or, I am also supposed to stand here? ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: प्लीज। ...*(व्यवधान)*...

DR. AKHILESH DAS GUPTA (Uttar Pradesh): There is a procedural mistake, Sir. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Withdraw all the security, Sir. ...*(Interruptions)*... The House is not in order. ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: सर, हम कैसे अपनी सीट पर बैठेंगे ? ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: आप अगली सीट पर बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*... मिश्र जी, यहां पर बहुत जगह है। ...*(व्यवधान)*... वह हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*... आप बैठ जाइए।*(व्यवधान)*... आप अपनी जगह पर जाइए। ...*(व्यवधान)*...

DR. V. MAITREYAN: They should leave the House. *(Interruptions)* They should not remain here. ...*(Interruptions)*...

श्री ब्रजेश पाठक (उत्तर प्रदेश): जब तक हाउस आर्डर में नहीं होगा, तब तक आप कैसे बहस करा सकते हैं? ...**(व्यवधान)**... सर, ऐसे बहस कैसे हो सकती है ? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please allow the Leader of the Opposition to speak. ...**(Interruptions)**...

DR. V. MAITREYAN: They should leave the House. ...**(Interruptions)**... They should not remain here. ...**(Interruptions)**...

श्री सभापति: आप प्लीज बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आपसे गुजारिश है आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): यह हाउस है या पुलिस थाना है ? ...**(व्यवधान)**... सर, हम यह जानना चाहते हैं कि यह हाउस है या पुलिस थाना है ? ...**(व्यवधान)**...

श्री वृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश): सर, क्या ऐसे सदन चलेगा ? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज आप चले जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप यहां मत आइए। आप यहां से नहीं बोल सकते हैं? आप अपनी जगह से बोलेंगे, आप अपनी जगह से बोलेंगे ? ...**(व्यवधान)**...

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Chairman, Sir, when I came to the House, today morning, I thought that, along with Members of this House, I would be a party to a great history in the making because we are all discharging a historical responsibility by becoming instrumental in legislating one of the most progressive legislations in recent times. On behalf of my party, let me state, at the very outset, that we all unequivocally support this law. But, then, Sir, this privilege, which we have all got, has been substantially diluted today. We have seen not one, but two histories in this House. The first, of course, will be a matter of privilege that we are enacting one of the most progressive legislations. The second is, and I have no doubt, all of us will hang our heads in shame because we have seen some of the most shameful incidents in India's parliamentary democracy. I only wish that the situation, by all concerned, should have been handled with a great deal of maturity and restraint. Thus, the privilege of enacting this particular law would have been far more enjoyable for all of us.

This debate on women's reservation, through a constitutional amendment, has been on for a decade-and-a-half. There is a myth that the reservations create a privileged class in the society. The truth is that the nature has created all of us as equals. Our Constitution provided for that equality but the situation in our society was such that some of our equals became unequals and the best evidence of that inequality is that 63 years after Independence, 50 per cent section of our society has at best 10 per cent representation in the Lok Sabha. In the State Assemblies also, the situation is not far different. Sir, today, we have all assembled here to enact a law or to initiate the process of enacting a law of affirmative action. The reservation quotas that we are going to provide for the women in the Lok Sabha and also the State Assemblies will become an essential instrument in giving a jump start to our object of equality which this country has always envisaged. Sir, we had the 15th General Elections to the Lok Sabha. The first 15 elections have seen between 7 per cent to 11 per cent women being elected to the Lok Sabha. वह संख्या जिसमें महिलाएँ चुन कर आती रही हैं, वह इन 15 चुनावों में सात फीसदी से लेकर 11 फीसदी तक रही है।

...(व्यवधान)... आज 63 साल बाद भी यह आंकड़ा मौजूदा लोक सभा में भी 10.7 परसेंट पहुँचा है। यह जो तर्क दिया जाता है कि बिना आरक्षण के...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: The House has taken a decision; it stands. ...*(Interruptions)*... यह हाउस का decision है, आप interrupt मत कीजिए। आप बोलिए, अरुण जी।...(व्यवधान)...

श्री अरुण जेटली: सभापति जी, यह जो तर्क दिया जाता है कि स्वाभाविक रूप से समाज जो आगे बढ़ रहा है तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी अपने-आप बढ़ता चला जाएगा, 63 वर्षों तक हमारे सामने जो अनुभव आया है, उसमें हमने देखा है कि 63 वर्षों तक यह परिस्थिति नहीं बदली और अगर यह कानून नहीं आता तो हम यह सम्भावना भी मान लें कि शायद अगले 63 वर्षों तक भी यह परिस्थिति नहीं बदलने वाली है।...(व्यवधान)... इसीलिए, आज यह आवश्यक हो चुका है कि भारत की संसद और विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी पूर्ण मात्रा के रूप में सामने आये। सभापति जी, हम देश को एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में बनाना चाहते हैं। आज हम वह देश हैं जिसकी अपनी परमाणु शक्ति है, but two-third of Indian children are born to women without medical help. ...*(Interruptions)*... आज जितनी कन्याएँ स्कूल छोड़ती हैं, who drop out, उनकी संख्या male child की तुलना में आ गयी है। अगर हम आज की परिस्थिति को देखते हैं, demographically, it is said that there are 933 women for every 1000 men in India. ...*(Interruptions)*... Our laws, some of them, in implementation, are still discriminatory as far as one section of the society is concerned. ...*(Interruptions)*... Sir, if you look at the state of our personal laws, a large number of our personal laws still have inequality ...*(Interruptions)*... I have always believed that it is the lesser participation of women in our Parliament and our State Assemblies which has still created ...*(Interruptions)*... a discriminatory position that we do not have the courage even to say that personal laws which violate the polity and dignity must all be replaced. ...*(Interruptions)*... Sir, we have practised enough the politics of tokenism as far as the system is concerned ...*(Interruptions)*... This politics of tokenism, Sir, ...*(Interruptions)*... requires to be replaced ...*(Interruptions)*... by the politics of ideas ...*(Interruptions)*... and the politics of ideas...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप लोग अपनी जगह वापिस जाइए, प्लीज़।...(व्यवधान)...

SHRI ARUN JAITLEY: ..must now translate ...*(Interruptions)*... into politics of representation as far as women are concerned.

श्री सभापति: आप लोग अपनी जगह वापिस जाइए, प्लीज़।...(व्यवधान)... You have no right to be in the well. ...*(Interruptions)*... Please go back to your places. ...*(Interruptions)*... आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है।...(व्यवधान)... आप अपनी जगह पर वापिस जाइए।...(व्यवधान)... आप लोग अपनी जगह पर वापिस जाइए ...*(व्यवधान)*... जो कुछ कहना है, बाद में कहिए, अभी जो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)*... देखिए, इससे कुछ नहीं होगा। हाउस का जो डिजीज़न है, वह हाउस तय करता है, आप तय नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*... आप interrupt कर रहे हैं, आप interrupt करना बंद कीजिए। देखिए, आप रूल्स से वाकिफ हैं ...*(व्यवधान)*... Please go back to your places. ...*(Interruptions)*...

श्री अरुण जेटली : सभापति जी, जो संविधान संशोधन पेश किया गया है, उसका जो सार है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। इस संविधान संशोधन में प्रावधान है कि 15 वर्ष के लिए देश की लोक सभा में और विधान सभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... आप लोग अपनी जगह पर वापस जाइए ...*(व्यवधान)*...

श्री अरुण जेटली: सभापति जी, इस एक-तिहाई आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक रोटेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। हर विधान सभा में और लोक सभा में एक-तिहाई सीटें हर आम चुनाव के अंदर आरक्षित की जाएंगी और अगले चुनाव के अंदर वे बदली जाएंगी। हम देखते हैं कि संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों में और अन्य पंचायतों में तथा local self bodies में जब से महिलाओं की भागीदारी आरंभ हुई है, उसका प्रत्यक्ष असर आज यह है कि इन 15-17 वर्षों के बाद हालांकि कानून में उनके लिए केवल 33 फीसदी आरक्षण है, लेकिन वास्तविकता में इन 15 वर्षों के बाद करीब 43 प्रतिशत महिलाएं आज ग्राम पंचायतों में चुने हुए पदों पर कायम हैं।

सभापति जी, अगर हम दूसरे देशों का अनुभव देखते हैं, तो आज यह कानून केवल भारत में नहीं आ रहा है, दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर यह प्रयोग में लाया गया है और दुनिया के विभिन्न देशों में इसको तीन अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया गया है। पहला सुझाव यह रहा कि कुछ देश राजनीतिक दलों के लिए एक पोलिटिकल पार्टी कोटा फिक्स कर लेते हैं। राजनीतिक दलों के लिए जो कोटा फिक्स होता है, उसके माध्यम से आरक्षण लेने का प्रयास करते हैं। कुछ देशों के अंदर लिस्ट सिस्टम के माध्यम से हुआ और कुछ देशों के अंदर ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं, जिनको आरक्षित किया जाता है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं और इन व्यवस्थाओं को अपने देश में लागू करने का प्रयास करते हैं, तो अनुभव में यह आया कि जिन देशों के अंदर चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है, यह प्रयोग सबसे ज्यादा उन्हीं देशों के अंदर सफल हो पाया है। दुनिया के जो पिछड़े देश हैं, अफ्रीका के देश हैं ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: आप लोग अपनी सीट पर जाइए ...*(व्यवधान)*...

श्री अरुण जेटली: Rawanda जैसे देश में वहां की संसद के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व दुनिया में सबसे अधिक हो गया है, क्योंकि वहां चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण किया गया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश, जहां चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण किया गया था, उन देशों के अंदर भी आरक्षण की प्रक्रिया सफल हुई। इस प्रयोग को जब हम अपने देश के ऊपर लागू करने का प्रयास करते हैं, तो इसके जितने भी आलोचक हैं और मेरे मित्र, जिनके अन्यथा विचार हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस पर हमारी जो धारणा है और उसका जो विश्लेषण है, वे उसे भी एक बार समझाने का प्रयास करें। राजनीतिक दलों के ऊपर कोटा बन जाए, यह सुझाव आता रहा है। शायद आज का जो संविधान है, उस संविधान की धाराएं जब मैं पढ़ता हूं, तो बिना उसको तब्दील किए हुए यह अपने देश में संभव नहीं हो सकता।

लेकिन जिन देशों ने लागू किया है, उनमें एक युनाइटेड किंगडम का उदाहरण है। आज युनाइटेड किंगडम के अंदर, राजनीतिक दलों के ऊपर कोटा लागू है। वे चुनाव क्षेत्रों के अंदर महिला उम्मीदवार उतारते हैं। उस कानून के अंदर कितनी संख्या है, इसका उसमें प्रावधान है। यदि आज हम वहां का अनुभव देखें, तो ब्रिटेन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तुलना में कम फीसदी महिलाएं हैं, जो उस प्रक्रिया के माध्यम से हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जीतकर आई हैं...*(व्यवधान)*... पाकिस्तान में चुनाव क्षेत्रों में लागू करना, अफगानिस्तान में चुनाव क्षेत्रों में लागू करना — जहां की महिलाओं को हम पिछड़ा मानते हैं, उनको अधिक प्रतिनिधित्व मिल पाया है, बनिस्पत युनाइटेड किंगडम जैसे देश में, जहां राजनीतिक दलों के ऊपर एक कोटा लागू हुआ था...*(व्यवधान)*... इसलिए मैं मानता हूं कि चुनाव क्षेत्रों द्वारा...*(व्यवधान)*... यह निश्चित करना ...*(व्यवधान)*... इस देश की वर्तमान भूमिका के अंदर ज्यादा सफल रहने वाला है। सभापति जी, यह आलोचना की जाती है कि ...*(व्यवधान)*... जो रोटेशन की प्रक्रिया है, उस रोटेशन की प्रक्रिया को नहीं रखना चाहिए। यह कानून पंद्रह वर्ष के लिए है। पंद्रह वर्ष में अगर तीन आम चुनाव होते हैं और हर चुनाव के अंदर अगर एक तिहाई सीटें आरक्षित रहती हैं, तो पंद्रह वर्ष के बाद महिला आरक्षण देश के माध्यम से हर चुनाव क्षेत्र तक पहुंच चुका होगा...*(व्यवधान)*... There will be a horizontal spread of women activism and women candidates across various constituencies and each constituency would have been represented

by women candidates at one point of time or other year. ...*(Interruptions)*... Now, when this, coupled with reservation in the Assemblies, local-self Governments and the Panchayats, is thrown open after this Amendment after 15 years from today, it will throw up millions of women activists who will be available to various political parties to contest. ...*(Interruptions)*... सभापति जी, यह भी आलोचना की गई कि यह आरक्षण देते वक्त समाज में कुछ और वर्ग हैं, जिनके लिए सब-कोटा रखना चाहिए। आज हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो एस.सी. और एस.टी. समुदाय हैं, उनके लिए चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है, किसी अन्य के लिए व्यवस्था नहीं है...*(व्यवधान)*... There is no provision for any other reservation of parliamentary and Legislative seats except Scheduled Castes and Scheduled Tribes. ...*(Interruptions)*... Those seats are already reserved amongst women constituencies also for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. ...*(Interruptions)*... You cannot possibly have reservations for communities or groups which are not provided in the larger election to have those reservations only for a sub-section of the constituencies as far as women are concerned. ...*(Interruptions)*... Sir, having said this, let me tell my friends in the Congress party that they must have a uniform practice across the country. ...*(Interruptions)*... आज देश की विभिन्न विधानसभाएं कानून बना रही हैं। एक तिहाई के स्थान पर, पचास फीसदी तक महिलाओं को ग्राम पंचायतों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आरक्षण दिया जा रहा है...*(व्यवधान)*... कई विधान सभाओं में बहुत सफलता से कई राज्यों में लागू हुआ है...*(व्यवधान)*... लेकिन जहां आपको पसंद नहीं आता...*(व्यवधान)*... गुजरात का उदाहरण है ...*(व्यवधान)*... चार महीने पहले कानून पारित हुआ था, लेकिन आज तक उस कानून को वहां के राज्यपाल स्वीकृति नहीं दे रहे...*(व्यवधान)*... इस प्रकार के दोहरे मापदंड कांग्रेस पार्टी द्वारा भी नहीं चल पाएंगे ...*(व्यवधान)*... सभापति जी, मैं यह मानता था, जो मैंने आरंभ में कहा...*(व्यवधान)*... कि आज हम इतिहास बनाने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*... It is a new gender justice history that we are writing and, therefore, we should all be enthusiastic in supporting it. ...*(Interruptions)*... But, at the same time, incidents, which have taken place to which a large number of people have contributed, I think, have soured our very spirit by supporting this legislation. ...*(Interruptions)*... All I said, while I unequivocally support this law, I cannot but unequivocally also condemn what has happened in the House today. ...*(Interruptions)*... We did not enter this House to see some of our colleagues being physically manhandled and being taken out of this House. ...*(Interruptions)*... It would have been better if we have been able to conduct it in a more congenial method. ...*(Interruptions)*... Sir, let us not forget that this country once passed the 42nd Amendment to the Constitution by imprisoning each person who was opposed to that Amendment...*(Interruptions)*... All those who opposed the 42nd Amendment could have opposed it but they were jailed during the Emergency. The effect was that the Emergency was lifted and that Amendment had to be revoked substantially. Therefore, our experience has been that even though I disagree with my friends who are protesting against this, we should give them a voice to be heard to vote against this law because an overwhelming majority — I believe, 85 to 90 per cent of us — is in support of this Bill. I would also appeal to my friends who are opposed to it to support it because a vast majority in this House is supporting the Bill.

You must also respect the spirit of democracy. If 85-90 per cent of the Members are supporting it, allow them to exercise the right of majority. A small minority group cannot

pressurise them into not allowing the proceedings to be conducted. And, therefore, you must impress upon your colleagues, who have been asked to withdraw from the House, to allow a congenial environment of this House to continue. You have a right to speak against this Bill; you have a right to dissent; but, certainly, you have no right to disrupt the mandate of the majority. If we respect each other, then I am sure this Bill would have been passed in the very spirit with which we have wanted. ...*(Interruptions)*...

Sir, I appeal to you while we unequivocally support this legislation, let us think in terms of steps that you must also initiate, so that a congenial environment can be created in this House; and those dissenting against us also have a voice to be heard as far as this House is concerned. With these words, I support this legislation. Thank you.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I rise to support the Constitution (Amendment) Bill. ...*(Interruptions)*...

Sir, I would like to begin on behalf of all the women of this country who have been waiting for over 62 years for justice, for reservation in this Parliament, for an equal voice in the development in this country, to thank the Congress President, Shrimati Sonia Gandhi, the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, and the entire UPA for bringing this historic legislation to vote, which no other party in 62 years has had the courage or the political will to deliver to the people of India. ...*(Interruptions)*...

Sir, I would like to point out in the two minutes that have been given to me that this is a logical continuation of Rajiv Gandhi's dream by which 33 per cent of seats were reserved in local bodies for women. As a result of which more than 10-12 lakh women are in local government bodies in every village in the country today. ...*(Interruptions)*... More than 50 lakh women have fought elections for those seats; and a large number of women in the villages are now enjoying the fruits of political power. ...*(Interruptions)*...

At that time as well, Sir, there were people who opposed reservation and sharing of political space by women. But the Indian National Congress, the Congress President, and the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, have never lagged behind in fulfilling the promise that was made in our manifesto. ...*(Interruptions)*... It was our solemn promise. ...*(Interruptions)*... Even yesterday, all the time, colleagues, both within and outside the House, doubted the commitment of this Government and made uncharitable allegations against us. We stand vindicated. We have fulfilled our promise to the women of this country. Sir, it is the promise of the UPA that women will get justice and women will get a share in development and a share in the political space and political decision-making of this country.

Sir, I would like to say this. Mr. Jaitley has already spoken. A wrong canard is being spread. Even those who oppose the Bill more strongly keep talking about reservation for *dalits*. I would advise them to read the Bill. There is reservation for *dalit* women in the Constitution

(Amendment) Bill and also for tribals. And that reservation has been mandated by the Constitution of India. I would also like to say that my party was the first party to reserve 33 per cent seats for women at all levels of the party structure. Therefore, we are totally committed to gender parity. Sir, I would also like to point out that it was our Prime Minister who introduced ...*(Interruptions)*... this piece of legislation. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप यहाँ से नहीं बोल सकते हैं ...*(व्यवधान)*...

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: And raised the 33 per cent of reservation at the local body level to 50 per cent. ...*(Interruptions)*... And now at the local government level, the quota has been raised to 50 per cent by the Cabinet.

Therefore, Sir, we have fulfilled our commitment and our mandate to the women of this country. Sir, I would like only to conclude by making two observations. People talk about equality. There can be no equality among unequals. The rights of equality of gender parity that have been mentioned in the Constitution are completely meaningless on the ground. Sir, Indian women fought shoulder to shoulder with men in response to the call from Mahatma Gandhi for freedom. Indian women went to jail; Indian women kept the home fires burning; and yet, Sir, after Independence, although the Constitution guarantees equality, Indian women lag far behind in education, health and so many other parameters of development. The way has been shown by the trailblazers at the local government level where Indian women who have been elected to local government have shown tremendous interest in basic issues like sanitation, education, child health and every basic issue to which attention needs to be paid for the development of this country. Therefore, Sir, when this Constitutional amendment is enacted and Indian women get an equal space in decision-making, the concerns of our women will be adequately represented in Parliament. And, I daresay, scenes like what we have seen today for which all of us apologise to you most unreservedly will never happen again and our democracy will be well set on the path of gender parity, on the path of development and on the path of true social justice because women cut across every community. Sir, women are the most deprived in every community and that lowest level will get justice finally. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Brinda Karat.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, before I speak, my colleague just wants to make a point.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, she is making a substantive contribution from my party, but, I just want to make one comment on behalf of my party CPI (M).

MR. CHAIRMAN: You are not listed here.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, with your permission, I will take two minutes of her time. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, on behalf of CPI (M), we are very honoured that we are part of this august House in making history in our country by enacting this legislation. Sir, I have stood up to make this point that it is not only acceding to demands of the women, but we are doing our social duty to the country by discharging this responsibility and that we are going to unleash a lot of hidden potential that is there, so far suppressed, in our country to build a better India. With that spirit, Sir, despite the fact that the ruling alliance does not have two-thirds majority in this House, all of us together, are supporting it to enact this legislation and create history in our country.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, with a sense of deep satisfaction, I stand in this House to offer the unstinting and unambiguous support of my party and also the women organisations with whom I have been working for the last several decades in support of this Constitutional amendment which is a very historic legislation that is certainly going to change the face of Indian politics. And, I believe, it is a change for the better. It is a change which will not only address the long-standing discrimination that women in India have faced in the political sphere, but also, I believe, Sir, it is path-breaking because it is going to deepen democratic processes. This is a legislation which ensures that the slogan of inclusion is transformed from rhetoric to guarantees — to legislative and Constitutional guarantees — and that is where the significance of this legislation lies. Sir, for 13 years or more, the women of this country have been fighting for such a legislation. And we have heard the most outrageous arguments against this legislation. We understand that when there are path-breaking measures of social reform, there is opposition. I recall today with pride the words of Dr. Baba Saheb Ambedkar when in the Lok Sabha, there was such a long debate on the Hindu Reform Bill, there was such strong opposition to that. He did say that no country can go forward which leaves the women behind. And, therefore, Sir, today, I believe, it is a memory of our male reformers, although I would hate to just say male as far as Dr. Ambedkar is concerned. But as far as gender is concerned, this is a fact of history that in India it has not been male versus female, and female versus male. But some of the greatest social reformers in our country have been male, and we believe that this role also can go forward only with the support of democratic male, democratic-minded male, and therefore, I believe it is only fitting today that I congratulate all the men in this House, all the men in the country who have supported the Bill. I am serious because I want to say that this is not a narrow approach of women versus men.

Sir, the other two, three points which I would like to make, and which I think are very much required, and that is, in our politics, I think, one of the most historic experiences in the Indian politics over the last two decades has been the role played by grass roots women in the panchayats. आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान की पंचायतों में जो सबसे गरीब औरतें हैं, उन गरीब औरतों को जब यह मौका मिला तो इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने गाँव के लिए, पंचायत के लिए, जिला के

लिए और ब्लॉक लेवल पर किस रूप में काम किया। उन्होंने यह अपने उत्थान के लिए नहीं किया बल्कि पूरे गाँव के उत्थान के लिए किया। यह एक रिकार्ड है। लोग कहते हैं कि इसमें प्रॉक्सी पॉलिटिक्स दिखाई देती है। मुझे पता है, मैं सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि सारे हिन्दुस्तान की पंचायत में एक नया phenomenon, प्रधान पति पैदा हो गया है। आज मैं चुनौती देती हूँ, अगर प्रधान पति होते हैं तो प्रधान पति का जो ...**(व्यवधान)**... जी?

श्री सीताराम येचुरी: पति-प्रधान।

श्रीमती वृन्दा कारत: अब पति प्रधान हो या प्रधान पति हो...**(व्यवधान)**... क्यों कि प्रधान तो महिला ही होती है। उसका पति तो केवल माला लगा कर पंचायतों में जाकर काम करता है। ...**(व्यवधान)**... यह मैं सही कह रही हूँ। इसीलिए मैं यह कहती हूँ कि आज हम सब लोगों को यह समझाना है कि प्रॉक्सी पॉलिटिक्स भी पुरुष प्रधान मानसिकता का एक reflection है। औरत काम करना चाहती है, लेकिन जब उसका पति वहाँ खड़ा हो जाता है और बी.डी.ओ. खड़ा होकर उसका हस्ताक्षर घर में ही करवा कर कहता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है तो उसके खिलाफ औरतें खड़ी होती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज हम उन लाखों औरतों को सलाम करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इस प्रकार का सही काम पंचायतों में नहीं किया होता तो आज हम लोगों की यह हिम्मत नहीं होती कि हम इस विधेयक को पास करते। इसलिए पंचायत की औरतों की भी इसमें एक जबर्दस्त भूमिका है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए।

सर, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ कि किसको श्रेय मिलना चाहिए इत्यादि, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहती हूँ और जयन्ती जी को यह सुन कर शायद अच्छा लगेगा कि 1988 में जब महिलाओं के लिए National Prospective Plan बना था तो उस समय ruling party की तरफ से एक सुझाव आया कि हम एक-तिहाई nomination के रूप में पंचायतों में देना चाहते हैं। सर, उस समय National Prospective Plan की debate में महिला संगठनों ने कहा कि हम किसी भी संस्था में backdoor से नहीं जाना चाहते हैं और ये वे महिला संगठन थे, जिन्होंने कहा कि we do not want nomination; we want elections. So, when we talk about the contribution today of various individuals and personalities, please do not forget that today, if the Bill is alive, it is because of the efforts of women's organizations, women's movement who kept reminding political parties that they cannot forget it, and it is they who we also have to salute today. I want to put this with the record, and I hope, if the Prime Minister is going to speak today, it will be so excellent if he could also salute those women's organizations and movements who have ensured that the Bill is alive.

Sir, I want to address two, three more issues. मुझे इस बात को सुन कर बहुत दुःख होता है जब यह कहा जाता है कि यह बिल केवल एक वर्ग की महिलाओं के लिए है। अगर हम अनुभव को देखते हैं तो हकीकत यह है कि जब हम आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की संख्या को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि राजनीति में ओ.बी.सी. की बेंटी होना कोई disadvantage नहीं है। आज बिहार के अंदर 24 महिलाओं में से 60% से अधिक पिछड़ी जातियों से हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 423 MLA हैं..

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: 403 हैं।

श्रीमती वृन्दा कारत: सॉरी, बिहार में 243 हैं, जिनमें से अगर आप संख्या को देखें, क्योंकि यह जो मिथ क्रिएट हो रहा है कि SC, ST और OBC को नहीं मिलेगा, मैं कहना चाहती हूँ कि यू0पी0 में 23 महिलाओं में से over 65% SC, ST, OBC और हमारी माइनॉरिटी की बहनें हैं। अगर हम बिहार में देखते हैं तो 243 सीटों में से केवल 24 महिलाएं हैं, जिनमें से वहां भी 70.8% या तो OBC, SC या हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं। इसलिए

यह कहना कि केवल जनरल कांस्ट की महिलाएं, जो बहुत सम्पन्न वर्गों से आती हैं, उन्हीं का यहां फायदा होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। आंकड़े यह दिखाते हैं कि जहां महिला रिजर्वेशन होता है, वहां निश्चित रूप से वे जो हमारी बहनें हैं, उनको और मौका मिलेगा, वे और आगे आएंगी। मैं मानती हूं कि मंडल कमीशन के बाद हिन्दुस्तान की पॉलिटिक्स में एक बुनियादी परिवर्तन हुआ जिनकी अपर कास्ट मोनोप्लीज़ थी, OBCs की सेल्फ मोबलाइजेशन से वह टूटा। यह एक सकारात्मक चीज थी, लेकिन उसमें OBC महिलाओं को वह हिस्सा नहीं मिला। आज हम यह गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आरक्षण होगा, महिला सीट अगर आप आरक्षित करेंगे तो जो पार्टियां कास्ट के आधार पर सीट देंगी, उसमें फर्क होगा — जाति का फर्क नहीं होने वाला है, कास्ट का फर्क होगा, भाई की बजाए बहन आएगी, लेकिन कोई परिवर्तन होगा, कास्ट कम्लेक्शन में कुछ परिवर्तन होकर कोई कन्वर्जन होगा कांस्टिट्यूशन गेरंटी आफ इक्वेलिटी का, यह होने वाला नहीं है, यह हकीकत है।

मैं यह मानती हूं आज कि हिन्दुस्तान की जनवादी प्रणाली में सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे माइनोंरिटीज़ की, हमारी संख्या बहुत कम है, हम मानते हैं। यह हमारे लिए, हरेक के लिए यह शर्म की बात है। क्यों हमारी माइनोंरिटीज़ इतनी कम हैं? क्यों आबादी के मुताबिक उनकी संख्या पार्लियामेंट में, स्टेट असेम्बलीज़ में नहीं हैं? निश्चित रूप पर यह हमारी कमजोरी है, कहीं न कहीं हमारे जनवाद में यह एक कमजोरी है। इस कमजोरी को हम कैसे दूर करें? अगर कोई सोचे कि इस कमजोरी को दूर करने के लिए महिला बिल एक जादू की छड़ी है, जिसे घुमाकर हिन्दुस्तान की जनवादी प्रणाली में जितनी भी कमजोरियां हैं, सब खत्म हो जाएंगी, यह होने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपने अनुभव से जानती हूं कि जहां महिला आरक्षण है, लोकल लेवल पर, हमारी माइनोंरिटी कम्युनिटी की बहनों को मौका मिला। सर, आप हैदराबाद को ही लीजिए। हैदराबाद में कॉरपोरेशन में 150 सीट्स हैं, वहां 50 सीट्स आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। उन 50 सीटों में 10 सीटों पर हमारी मुस्लिम बहनें चुनाव लड़कर जीतकर आई हैं। क्यों जीतकर आई हैं? क्योंकि वे सीटें महिला आरक्षित सीटें थीं। इसलिए, महिला रिजर्वेशन का फायदा उठाकर हमारी बहनें खड़ी हो सकती हैं, जीत सकती हैं और आज मैं यह उम्मीद जताती हूं कि महिला आरक्षण के बाद निश्चित रूप से जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, पिछड़ी हैं, माइनोंरिटीज़ हैं, SC हैं, ST हैं, निश्चित रूप से उनको इसका फायदा मिलेगा और मैं पोलिटिकल पार्टीज़ से भी यह अपील करना चाहूंगी कि इस आरक्षण का फायदा उठाकर उन महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करना अनिवार्य है, मैं यह भी कहना चाहती हूं।

सर, रोटेशन के बारे में लोगों ने कहा कि यह रोटेशन क्या है, यह रोटेशन बिल्कुल गलत है, लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं कि एक कांस्टिट्यूएन्सी में जहां ढाई या तीन लाख वोटर्स हैं, वहां क्या एक ही प्रतिनिधि है, जो जिंदगी भर, जब तक जीएगा, वहीं प्रतिनिधित्व करेगा। क्या वहां और कोई नहीं है, और कोई काबिल नहीं है? यह बिल्कुल गलत समझ है। हम लोगों की पार्टी में, हम लोगों ने कोशिश की कि हम कम से कम दो टर्म, राज्य सभा में तो दो टर्म हमने लागू कर लिया, लेकिन लोक सभा में भी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारा यह प्रयास है कि कम से कम दो या तीन टर्म के बाद कोई और साथी आए और करे। चूंकि हम यह नहीं मान सकते, मोनार्की के खिलाफ है, लेकिन इन्डायरेक्ट मोनार्की है कि भइया, हम एक बार जीते तो हम कभी नहीं इससे हट सकते और अगर हटेंगे तो लोग कहेंगे कि इनस्टेबिलिटी होगी।

That is the stability of democracy that you have more and more people who can take the responsibility. मैं बता रही हूं, मैंने “प्रयास” शब्द का इस्तेमाल किया है और इसीलिए मैं कहती हूं कि यह अनिवार्य है और यह बात सही है, जो अरुण जेटली जी ने कही कि horizontal spread of reservation. We don't want monopolies to develop that only in one constituency there will be reservation and only that one constituency that women can develop. We want horizontal strength of development by

women leaders just as has happened in panchayats where because of merit — please remember those of us who talk about merit — we are over 33 per cent. In many panchayats, we are 40 per cent. I don't want to scare you too much. I certainly hope that in the Assemblies and the Parliament also very soon women, through their own work, capacity and sacrifice, will cross 33 per cent and reach 40 per cent or 50 per cent. This is a promise.

MR. CHAIRMAN: Please keep an eye on the watch.

SHRIMATI BRINDA KARAT: I am keeping an eye on the watch. मैं चेयर को भी address कर रही हूँ और मैं बाकी सदस्यों को भी address कर रही हूँ।

SHRI SITARAM YECHURY: Should we keep a watch on the time or on the numbers, Sir?

श्रीमती वृंदा कारत: सभापति जी, मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहती हूँ कि लोग पूछते हैं कि बिल के बाद क्या होगा, क्या पूरी पोलिटिक्स बदल जाएगी, क्या करप्शन खत्म हो जाएगा, क्या सब कुछ हो जाएगा? हम कहते हैं कि औरत कोई super woman नहीं है कि वह पार्लियामेंट में आएगी और पूरी दुनिया और देश को बदल देगी, हालांकि उसमें ताकत है बदलने के लिए। मैं यह कहना चाहती हूँ कि that don't expect women to treat themselves superwomen just to fight against the discrimination which is there in politics. I don't think it is required for us to prove that by fixing 33 per cent for women that they don't want to reach there. However, I do believe that the entry into the electoral politics is most definitely going to lead to a more sensitive politics and we believe it is going to be our efforts that the core political agenda, the so-called hard issues and the soft issues...

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, this is the problem. What are the hardships? What are the core political issues? Is not violence against women a core political issue? Is not female foeticide a core political issue? Yet, when these are discussed, these are not considered to be core political agenda. Many people asked: Why is there only one-third? It is a threshold. It is a critical mass which is going to affect the policy and, therefore, I believe it will change. Lastly, Sir,...

MR. CHAIRMAN: No. Your time is over, Mrs. Karat.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Yes, Sir. Just a little bit of indulgence since you make so much of adjustments. One more point. I believe, all this is also going to change the culture because women today, whether we accept it or not, in most of the modern societies, are still caught in a cultural prism. To be an equally independent citizen we have to fight every day. ...(*Time-bell*)... In our country, in the name of tradition, in the name of culture, stereotypes are imposed and, I believe, when so many women are there in public life, these stereotypes and cultures, those bars, which imprison women will also be broken.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Therefore, I once again congratulate the House and I do express my disappointment that the floor management yesterday was very poor.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI BRINDA KARAT: You didn't take everyone into confidence. When I believe, Sir, ...

MR. CHAIRMAN: Please conclude. I am afraid I can't allow you any more time.

SHRIMATI BRINDA KARAT: ... I also hope there will be no delay in the Lok Sabha passing it. Don't do it that नाम के वास्ते राज्य सभा में कर लिया भइया, लेकिन लोक सभा में क्या दिया?

MR. CHAIRMAN: Please. Please observe time.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Please don't do that. We want this Bill to be passed in the Lok Sabha in this session itself. Thank you.

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: माननीय सभापति महोदय, हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपके समक्ष यह रखना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला हैं और बहुजन समाज पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। बहुजन समाज पार्टी का यह मत है कि अगर महिलाएं पचास फीसदी हैं, तो 33 फीसदी reservation क्यों किया जा रहा है? महिलाओं के लिए पचास फीसदी आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के अनुपात को देखते हुए 33 फीसदी reservation की बात करके महिलाओं के साथ discrimination करने की बात इस बिल में कही गई है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। अगर आप बराबरी पर लाना चाहते हैं, तो जो उनका अनुपात है, उसके हिसाब से बराबरी पर लाना चाहिए, पचास प्रतिशत के हिसाब से लाना चाहिए। इसके अलावा इस बिल के संबंध में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखकर यह बात कही कि महिला आरक्षण पर जो बिल आया है, उसमें कुछ कमियां हैं। इसलिए इन कमियों को पहले दूर करना चाहिए और तब इस बिल को यहां पर पेश करना चाहिए। इस तरीके से बिल को नहीं लाना चाहिए। जो कमियां इंगित की गई हैं, उन कमियों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि महिला आरक्षण में आप किन महिलाओं के लिए आरक्षण करना चाहते हैं? महिलाओं को आप आरक्षण इसलिए देना चाहते हैं कि जो महिलाएं socially, educationally, economically backward हैं, जिनको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है, उस वर्ग के लोगों को आगे आने का मौका दिया जाए। ऐसी महिलाओं को opportunity मिले और वह संसद में भी आ करके और विधान सभा में अपने पचास प्रतिशत अनुपात के साथ में अपनी भागीदारी कर सके। ऐसी महिलाएं कहां पर हैं? ऐसी महिलाएं दलित वर्ग में, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBC, Backward Class और Minorities में हैं, जिनको कि आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है और सवर्ण जाति में भी जो महिलाएं educationally backward हैं, economically backward हैं, ऐसी महिलाओं को आगे आने की opportunity मिलनी चाहिए। अगर आप reservation कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आपको अलग से Quota फिक्स करना चाहिए कि आपको भी पूरा मौका मिलेगा और आपके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं कि आप भी सामने आए। लेकिन इसकी जगह आपने इसमें जो reservation किया है, जैसा कि श्रीमती जयन्ती नटराजन जी कह रही थी और श्री अरुण जेटली जी कह रहे थे कि इसमें Scheduled Castes, Scheduled Tribes के reservation को लेकर विरोध हो रहा है। यह गलत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बिल में जो reservation किया गया है, आपने इसमें कोई extra चीज नहीं दे दी है कि जो आप बताना चाहते हैं कि Scheduled Castes, Scheduled Tribes को दे दिया है। उनके लिए जो reservation है, वह reservation तो जो पूरी सीटें हैं, उनमें से निकाल कर आप दे रहे हैं। अब आप क्या करने जा रहे हैं? उन्हीं में से काट कर इस बिल के तहत Scheduled Castes, Scheduled Tribes वर्ग को reservation यहां पर देंगे, तो जो इस category के लोगों का main reservation है, उसको कम करके यहां

पर देने जा रहे हैं, जिसका कि हम विरोध कर रहे हैं। हमारा यह कहना है और हमारी पार्टी की यह मांग है, हमारी पार्टी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है, उसमें भी इस बात को लिखा है कि उनको जो reservation दिया जाए, इस वर्ग की जो महिलाएं हैं, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, economically और socially backward class की जो महिलाएं हैं और Upper castes तथा Minorities में भी जो इस category में आते हैं, उनके लिए आप reservation अलग से, जो category 33 percent आप अगर दे रहे हैं, हमारी मांग है कि आप पचास प्रतिशत दीजिए, लेकिन इसके तहत आप इनके लिए जो reservation करें, तो जो मुख्य reservation पहले से है, उसमें से काट कर के reservation नहीं दें। आपको वह reservation बरकरार रखना चाहिए। अगर आप उसमें से काट कर दे रहे हैं, तो कोई खैरात नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस वर्ग के लोगों को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान के जन्मदाता हैं और जिन्होंने संविधान को बनाने में बहुत योगदान दिया, उन्होंने right of equality का अधिकार संविधान में दिया है, Congress ने अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं किया है। ठीक है, आप दलितों का उत्थान नहीं चाहते हैं। आपने इतने वर्षों में दलितों का उत्थान नहीं किया है, उनको पीछे ढकेलने का काम किया है। Backward Class के लोगों को पीछे ढकेलने का काम किया है। डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को भी “भारत रत्न” पाने के लिए कितने वर्ष लग गए। 1990 में जब कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं थी, तब जाकर उनको “भारत रत्न” मिल पाया। इस बात का सबको ज्ञान है कि Congress का दलितों के लिए कितना प्रेम है। लेकिन इस बिल को लाकर आपने अपना यह व्यवहार और उजागर कर दिया है। आपने यह दिखाया है कि जब इन महिलाओं को आप अलग से रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो इस तरह से इनको आप आगे नहीं बढ़ने देंगे। बिल में आप कह रहे हैं कि हम रोटेशन करेंगे, पांच साल में आप रोटेट कर देंगे। आप एक महिला को जिस constituency में पांच वर्ष के लिए काम करने का मौका देंगे, उसको पहले ही दिन बता देंगे कि आप पांच साल के बाद इस constituency में काम नहीं कर सकती हैं और आप सिर्फ पांच साल के लिए यहां पर हैं। इससे यह होगा कि वे पहले ही दिन अपनी क्षमता से कमजोर हो जाएंगी। इस तरह से इस बिल में एक नहीं, अनेकों खामियां हैं, लेकिन जल्दी में आप बिल ला रहे हैं। आप बिल ला सकते थे, बिल लाने से पहले इन चीजों को देख सकते थे। पिछली बार भी जब बिल लाने की बात हुई थी, ऐसा नहीं है कि हम लोग यह बात कोई आज ही कह रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी पहली बार ऐसी बात कह रही है, इसके पहले भी जब आप यह बिल लाए थे, तब बहुजन समाज पार्टी ने आपके सामने यह बात रखी थी कि आप इनको 33 प्रतिशत आरक्षण दीजिए। अगर आप 33 प्रतिशत ही आरक्षण लाना चाहते हैं, 50 प्रतिशत देने की मंशा अगर आपकी नहीं है, तो 33 प्रतिशत में आप Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, minorities और upper castes की महिलाएं, जो educationally backward हैं, economically backward हैं, उनके लिए आरक्षण घोषित कीजिए और जब आरक्षण घोषित कीजिए, तो हमारा जो main आरक्षण Scheduled Castes and Scheduled Tribes का है, उसको disturb नहीं कीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद भी आपने ऐसे बिल को यहां पर पेश करने का काम किया, जिस बिल में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि आरक्षित category की जो महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देने की जगह आप लिमिटेड लोगों को, ऐसे लोगों को, जो इस category में नहीं आते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप इस बिल को पेश कर रहे हैं। अतः हमारी यह मांग है कि इस बिल पर वोटिंग कराने से पहले या इसे पास कराने से पहले आप इसको दोबारा देखें। दोबारा देखकर इसमें संशोधन लाएं और संशोधन लाने के बाद आप इस बिल को दोबारा पेश करें, तब हम आपको पूरा समर्थन देंगे, लेकिन अगर आप इसको यहां पर इस तरीके से नहीं लाते हैं या आप ये अमेंडमेंट्स नहीं लाते हैं और रिजर्वेशन के नाम पर यह जो दलित विरोधी बिल आप लाए हैं, अगर आप इसको वोटिंग के लिए भी पेश करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करेगी, क्योंकि इसमें आपने आरक्षण में minorities का विरोध किया है, आपने उनका ध्यान नहीं रखा है, आपने Scheduled Castes and Scheduled Tribes का ध्यान नहीं रखा है,

आपने Backward Class का ध्यान नहीं रखा है। जिन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका न मिले और जहां पर वे हैं, उससे और पीछे उनको धकेल दें, इस तरह की आपकी मंशा है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा.... जैसे कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पत्र लिखकर आपसे मांग की थी, मैं दोबारा मांग करूंगा कि आप इस बिल को दोबारा देखें और देखने के बाद इन चीजों पर गौर करके, इस बिल को संशोधित करके, दोबारा से House में रखें, तब बहुजन समाज पार्टी आपका पूरा समर्थन करेगी, वरना बहुजन समाज पार्टी इस बिल का इस condition में समर्थन नहीं करेगी।

DR. V. MAITREYAN: Mr. Chairman, Sir, on behalf of my party, the AIADMK, and on behalf of the General Secretary of my Party, Dr. Puratchi Thalaivi, we extend our whole-hearted support to the Women's Reservation Bill. Yesterday was to be a historic day. But history is being made, at least, today. Pandit Jawaharlal Nehru once said, "To watch history is good. But to be a part of the history is even better." And, we are proud to be a part of the history as is being made when this historic Bill is being passed today.

Sir, we are very sorry to be a witness to the various incidents which have happened yesterday and today, and I, on behalf of my party, sincerely apologise to the Chairman for whatever has happened.

I gladly recall that when the AIADMK was a part of the Central Government, in 1998-99, during the NDA regime, my party colleague, Dr. Thambi Durai, who was the then Union Law Minister, had an opportunity to pilot the Bill on the Women's Reservation Bill. Mr. Chairman, Sir, when India attained independence, people in the Western democracies were stunned on one singular issue, that is, the issue of Universal Adult Franchise. When many people believed that democracy was being incubated there, the West did not give Universal Adult Franchise to their women. There were restrictions on the women to vote and express their freedom of choice. Great Britain, Germany, France, Switzerland and even the U.S. successfully relented and reversed their decision on the Universal Adult Franchise only in the second half of the 20th Century. So, it is no wonder that the world was stunned to see the founding fathers of the Indian Constitution work out the universal adult franchise without virtually any discussion of discrimination against the weaker sex.

India is one ancient land that has acknowledged the feminine divinity and the divinity in the feminine. Though apparently separate issues, these two concepts are intricately woven and are symbiotically interlinked to each other. The Western civilization is still in the formative years, as far as these concepts are concerned. It is, therefore, natural for an Indian male to recognize the power of mathru-shakti, while his counterpart in the West feels shy of recognizing that. No wonder, we celebrate Indian women and they celebrate and worship women. And this idea cuts across castes and communities in India, making it the most secular idea in modern India. In the mid-sixties, when Panditji and Lal Bahadur Shastriji died in quick succession, the mantle of leading the country fell on Indira Gandhi. The West, as well as the rest of the world, perhaps, with a few exception of certain Asian countries, was aghast. The reason was, how could a

woman lead a country that too, as vast and complicated and convoluted as India. But, Indira Gandhi, not only led India for sixteen years but several times she took on the might of the world as only an Indian woman could do. Who can forget the big snub to the U.S. in the height of creation of Bangladesh? No wonder, Shri Vajpayeeji equated Indiraji as Mata Durga.

The rich tradition of Indian women occupying the political leadership continues from then on. My leader, Dr. Puratchi Thalaivi is the most towering woman leader from the South. Similarly, the Congress Party, the Trinamool Congress and the Bahujan Samaj Party are some of the major political parties which are headed by women. It is not only that women have been dominating the political scene. There are several women who have been dominating the literary, arts, films, science, sports and what not. On this great occasion, on behalf of my party, and my party General Secretary, Dr. Puratchi Thalaivi, I salute all the women who have done India proud. Much as we celebrate the Indian women, there is one class of Indian woman who is uncelebrated, unrecognized and un-debated. It is the Indian housewife. It is the power of this lady that propels every single house in India. Her dexterity in handling the finances of the house far exceeds the ability of all the Finance Ministers of the Government of India. Undeterred by all odds, she has ensured that Indian households are far more viable than even the Government of India. Today, the Indian domestic savings stands at approximately 37 per cent of the GDP. Today the Indian domestic savings approximately funds 90 per cent of the Indian investment requirement, virtually making India less dependent on the FDI than all other peer countries. All these have happened simply because of the innate discipline of the Indian housewife of managing the Indian households.

The West is in deep economic crisis and also in financial crisis. And the reason for the same is that while the West has liberated its women, the women have liberated themselves from the responsibilities of the family. The net result is the gargantuan spending with little or no savings. In contrast, the Indian women may not be liberated in the strictest sense of the term, but have carried with far more responsibility, dignity and discipline than their western counterparts. In short, the Indian model of preserving the space for women in the society by providing her respect instead of rights is the singular distinction between our society and the western society.

It is, therefore, incumbent that we continue to preserve this — not as a right to women but as a mark of respect by the society to the contribution by the Indian women to the development of our country for the past five thousand years of recorded history.

Realizing the need for gender equality in politics, the AIADMK under Dr. Puratchi Thalaivi played a pioneering role by reserving 33% of all party posts for women as early as in the 1990s. It was when Madam was the Chief Minister of Tamil Nadu that the Cradle Baby Scheme was first introduced in 1990s to prevent female infanticide under which the State adopted abandoned female infants.

It was under Dr. Puratchi Thalaivi that all women police stations were introduced in Tamil Nadu in 1992 to exclusively handle cases relating to the offences against women, particularly domestic violence.

It was again she who constituted an exclusive commandor battalion comprising only women. She also accorded the maternal role of woman the due legal recognition by legitimizing the rule of one's mother's name as the initial instead of or in addition to the father's name. Again, it was Puratchi Thalaivi who provided impetus for the growth of woman's self-help groups to make women economically free.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

DR. V. MAITREYAN: Our party, headed by Puratchi Thalaivi, in our election manifesto for the Parliamentary elections in 2009, made a provision for 33 per cent women in the Lok Sabha polls. We reiterate that this is not a right conferred upon the women of India; rather, it is recognition of the fact that India is feminine, her economy is feminine, and her soul is feminine.

It is a small tribute made out by the people of this great country to the better-half of India. To this extent, AIADMK whole-heartedly supports this Bill.

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : सभापति महोदय, मैं जनता दल यूनाइटेड की ओर से इस वूमेन रिजर्वेशन बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, हमको इस बात का फख है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार है, वह सरकार चल रही है। वह पहली ऐसी सरकार है जिसने औरतों को 50 परसेंट आरक्षण देने का काम किया है। मुझको इस बात की भी खुशी है कि उसका अनुकरण न सिर्फ कई राज्य सरकारें कर रही हैं, बल्कि केन्द्र सरकार ने भी पंचायती राज में 33 परसेंट आरक्षण को 50 परसेंट करने का निर्णय लिया है। हम लोगों को इस बात की खुशी है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

उपसभापति महोदय, हम लोग आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग काफी दिनों से करते आए हैं और उसके पीछे हमारा एक तर्क रहा है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जाति व्यवस्था वाला समाज है और पैदाइश के आधार पर गैर-बराबरी को हमारे समाज में लम्बे समय से मान्यता रही है। उसी का परिणाम है कि 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, आपने देखा होगा लोक सभा में जो ओ0बी0सी0 है, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व मात्र 12 प्रतिशत था, ऐसे हिन्दी बैल्ट से 64 प्रतिशत ऊंची जाति के लोग लोक सभा में जीतकर आते थे, यह स्थिति थी। लेकिन वोट की राजनीति ने इस स्थिति को बदला और धीरे-धीरे जो अन्य पिछड़ी जातियां जिनकी तादाद ज्यादा थी, जिनकी संख्या ज्यादा थी, उनका प्रतिनिधित्व लोक सभा में बढ़ने लगा। आपको जानकर खुशी होगी कि 1977 में जब पहली दफे कांग्रेस की सरकार दिल्ली से हटी उसके बाद ऊंची जातियों का प्रतिनिधित्व घटा और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व लोक सभा में बढ़ा। आज यह हालत है कि लोक सभा में 30 प्रतिशत से ज्यादा ओ0बी0सी0 के सदस्य उपस्थित हैं। यह वहां स्थिति है। ऊंची जाति के लोग जो वहां 64 परसेंट से ऊपर सिर्फ हिन्दी बैल्ट से आते थे, आज उनकी तादाद 33 परसेंट और उससे भी कम हो गई है। यही हाल सारे राज्यों में हुआ है। हमको लगता है कि शायद हिन्दुस्तान में एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जो उल्टी दिशा में चल रहा है। 1972 से 1996 के बीच में अगर आप वेस्ट बंगाल असेंबली के सोशल कम्पोजिशन को देखेंगे तो वहां 38 परसेंट से 50 परसेंट तक ऊंची जाति के लोगों का रिप्रजेंटेशन हो गया है। बाकी राज्यों में ऊंची जाति का रिप्रजेंटेशन घट रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां 30 वर्षों तक क्रांतिकारी सरकार रही है, वहां पिछड़ी जातियों की तादाद घटी है और 50 फीसदी ऊंची जातियों का वहां

प्रतिनिधित्व हो गया है। यही नहीं, उपसभापति महोदय, जो वहां का मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में भी देखिएगा कि 50 परसेंट से अधिक लोग वे सिर्फ एक ही बिरादरी, वैद्य बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी इन दो-तीन बिरादरियों में से हैं। यह फेक्च्युअल स्थिति है। आरक्षण के भीतर आरक्षण हम अब भी चाहते हैं, लेकिन किस का? ओ0बी0सी0 एक बहुत बड़ा तबका है और ओ0बी0सी0 में ऐसी-ऐसी जातियां हैं, एक तो जिनका संख्या बल ज्यादा है, जिनको हम मिडिल कॉस्ट कहते हैं और ऐसी भी जातियां हैं जो छोटी-छोटी संख्याओं में, अनेकों जातियों में बंटी हुई हैं, वे चुनाव लड़ नहीं पाती हैं। हमको इस बात का फख है कि बिहार में हमारी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकायों में जिनको एक्सट्रीमली बैकवॉर्ड कहा जाता है, अति पिछड़ी जातियों में कहा जाता है, उनको हम लोगों ने आरक्षण दिया। इस आरक्षण का यह नतीजा निकला कि हमारे यहां समाज का लोकतांत्रिकरण हुआ और जो हमारा उग्रवाद है, वह इसकी वजह से कमजोर हुआ। हमारे यहां जो उग्रवाद था, हम लोगों ने उसकी रीढ़ को भी कमजोर किया। जो उग्रवाद का सामाजिक आधार था, जहां से उनको ताकत मिलती थी, उस ताकत को हम लोगों ने कमजोर किया। हमारे यहां ऐसी-ऐसी जातियों के लोग प्रमुख बने हैं, जिला परिषद् के अध्यक्ष बने हैं, जो वार्ड का चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम यह चाहते थे कि ऐसी जातियों को चिह्नित किया जाता और उनको इस आरक्षण में जगह दी जाती। मैं एक गंभीर और महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं, यहां पर प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं, उनके सामने कहना चाहता हूं। मैंने कई मुसलमान साथियों से बात की है और मैं आपको ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उनके मन में इस बात की आशंका है कि आज का जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में, आबादी के अनुपात में उनके प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। लोक सभा में मुस्लिम समाज के 27 या 28 लोग हैं और 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी 13.4 है। उनके 60 या 62 प्रतिनिधि होने चाहिए थे, जबकि वे कुल 27 या 28 हैं। उनको इस बात की आशंका है कि यह जो महिलाओं का आरक्षण होगा, तो उसमें करीब 279 या 280 जनरल सीट लड़ने के लिए होंगे। उनका यह कहना है कि हमारे मर्द तो जीत नहीं पाते हैं। हमारे यहां मुस्लिम महिलाएं कितनी हैं, तो इससे हमारी तादाद और घट जाएगी। उनमें एक प्रकार से अलगाव की भावना पैदा हो रही है। आपको याद होगा pre independence era में जब यह सवाल उठा था कि इस तरह का लोकतंत्र आएगा, वोट का राज होगा तो बहुमत में हिन्दू हैं, हम मुसलमान माइनोरिटी में हैं, हमको हमारा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। यह जो उनके मन में आशंका थी, उस समय उस आशंका को देश का नेतृत्व निर्मूल नहीं कर पाया, उसका नतीजा हुआ कि देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के बाद भी संविधान सभा बैठी हुई थी, उस संविधान सभा में कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसको उठाया था कि जिस तरह से अंग्रेजों के समय में एक मुसलमानों का सेप्रेट इलेक्टोरल था, वह आजादी के बाद भी उनको मिले। आप उस Constituent Assembly की डिबेट को पढ़िए प्रधान मंत्री जी, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से धमकी देकर मुसलमानों को चुप करा दिया गया। उनके मन में जो आशंका है, उस आशंका को निकालने का इंतजाम भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो देश का जो वातावरण है, इतनी ज्यादा आबादी, 13.6 प्रतिशत आबादी, इस आबादी की मन में आशंका हो कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमको इन्साफ नहीं मिल रहा है, तो यह देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। रंगनाथ मिश्र कमेटी ने, जो मुसलमानों में दलित जातियां हैं, उनको भी हिन्दू दलित जातियों के समान आरक्षण देने की बात कही है। आज जो शैड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन असेम्बली और पार्लियामेंट में है, उसका लाभ मुस्लिम समाज के कुछ तबके को मिल सकता था। ...**(समय की घंटी)**... ये जो आशंकाएं हैं, इन आशंकाओं को आपने दूर किया होता, इन आशंकाओं को आपने इस बिल में दूर किया होता, तो यह बिल ज्यादा बेहतर बनता। मैं एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे साथी विरोधी दल के नेता, श्री अरुण जेटली जी ने कहा कि बेहतर है, सबसे बेहतर है कि आप जो आरक्षण देने जा रहे हैं, इस आरक्षण के बारे में ऐसा कानून बनाइए कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कम्पलसरी हो जाए कि 33 परसेंट उम्मीदवार वे महिलाओं को बनाएं। ...**(समय की घंटी)**... ये जो आप रोटेशनवाइज सीटें रिजर्व करने जा रहे हैं, पंचायतों में हमने इसको रोटेशनवाइज किया था, उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आया, उसको हम लोगों को बदलना होगा।

श्री उपसभापति : तिवारी जी, आप समाप्त कीजिए। श्री तारिक अनवर ।

श्री शिवानन्द तिवारी इसलिए बेहतर होगा, ज्यादा उम्मीदवार महिलाएं बन पाएंगी, अगर आप इलेक्शन लॉ में परिवर्तन करके पार्टियों के ऊपर बंदिश लगा दें कि हर पार्टी को 33 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाओं को बनाना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो सुझाव आया है, ... (समय की घंटी)... उस सुझाव को आप इस बिल में इनकारपोरेट करेंगे, ताकि सब लोग उत्साह के साथ इस बिल का समर्थन कर सकें। इसी के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल): सर, पश्चिमी बंगाल में जात-पात का भेदभाव बहुत ही मामूली है और जो झगड़ा होता है, उसको वे लोग अपनी समझदारी से हल करते हैं।

جناب محمد امين : سر، پشچہمی بنگال میں جات پات بھید بھاؤ بہت ہی معمولی ہے اور جو جھگڑا ہوتا ہے، اس کو وہ لوگ اپنی سمجھداری سے حل کرتے ہیں۔

श्री उपसभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी एन०सी०पी० की ओर से इस ऐतिहासिक संशोधन बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, आजादी के बाद लम्बा समय बीत जाने के बाद, लगभग 63 वर्ष बीत जाने के बाद आज यह संशोधन हम करने जा रहे हैं। .. लेकिन देर आयद, दुरुस्त आयद। कहावत है कि जब आख खुले, तभी सवेरा है। मैं समझता हूँ कि महिलाओं को उनका यह राजनीतिक अधिकार — बहुत पहले मिलना चाहिए था। देर से ही सही, लेकिन आज हम इस फैसले पर, नतीजे पर पहुँचे हैं। जहाँ तक पंचायती राज की बात कही गई, यह बात सही है कि हमारे पास एक उदाहरण है कि जब पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो जो महिलाएं अपने आपको यह महसूस करती थीं कि उनको समाज में, देश की राजनीति में, देश की सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है, उन्होंने उस आरक्षण का लाभ उठाया। उन्होंने हमारे पंचायती राज में, लोकल बॉडीज में, जिला परिषद में जिस प्रकार से नेतृत्व संभाला और धीरे-धीरे अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, उससे यह सिद्ध होता है कि उनके अंदर वह क्षमता है, वह सलाहियत मौजूद है। बार-बार यह जो कहा जाता है कि राजनीति औरतों के बस की बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि वह बात बहुत पुरानी हो चुकी है। यह बात सही है कि हमारी आबादी की लगभग पचास प्रतिशत आबादी महिलाएं हैं। जब तक इन पचास प्रतिशत महिलाओं को देश की राजनीति में और देश की सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, तब तक एक मजबूत भारत का, एक शक्तिशाली भारत का हमारा जो सपना है, वह सपना साकार नहीं हो सकता है। जब तक देश की मुख्यधारा से इस पचास प्रतिशत आबादी को नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक यह संभव नहीं है। मुझे खुशी है कि आज हम यह फैसला ले रहे हैं, यह ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहे हैं। अच्छा यह होता कि यह बिल आम सहमति से पास किया जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपना मन बना लिया था कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। यहाँ तर्क दिया गया, बहुत तरह की बातें कही गईं, पिछड़े वर्ग और ओ.बी.सी. की बात कही गई, अल्पसंख्यक समुदाय की बात कही गई, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि इसके पीछे उनकी नीयत साफ नहीं थी। वे उसमें सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ देख रहे थे, वे पोलिटिकल कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वृंदा जी ने ठीक कहा कि यह महिलाओं का सवाल है। उन्होंने आंकड़े बताए कि पंचायती राज और लोकल बॉडीज में जो इलेक्शन हुए, उसमें पिछड़े वर्ग, ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं, उसमें उनकी भागीदारी आई है और इससे यह सिद्ध होता है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वे यकीनन आगे आएंगी। राजनीतिक दलों का काम यह है कि उनको प्रोत्साहित करें — अल्पसंख्यक की बात ठीक है, हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय में पर्व सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद आज मुस्लिम महिलाएं आगे आ रही हैं। आज तमाम राजनीतिक दल उनकी तरफवारी की बात कर रहे हैं, अगर सही मायनों में उनको प्रतिनिधित्व

† [Transliteration in Urdu Script]

दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वे आगे आएंगी। जो ओ.बी.सी. की बात कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहे हैं, ये सभी वे राजनीतिक दल हैं, जो किसी न किसी रूप में सत्ता में रहे हैं, ये दल राज्यों में सत्ता में रहे हैं। जब उनको सत्ता भोगने का मौका मिला, तब उनको ध्यान नहीं आया कि इस सेक्शन के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उनको मौका दिया जाए। वे परिवारवाद से ग्रस्त हैं। वे उससे ऊपर कभी भी नहीं उठ पाए, लेकिन आज बड़ी-बड़ी बातें और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं इतना ही चाहूंगा कि आने वाले समय में यह बिल सही मायनों में हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक लंबे समय से महिलाओं का जो शोषण हो रहा था, उनका राजनीतिक शोषण हो रहा था, इसके जरिए उनको उससे निजात मिलेगी और आने वाले समय में भारत की जो तस्वीर है, वह उभरकर सामने आएगी। हम दुनिया को यह बता सकेंगे कि भारत हिंदुस्तान; हिंदुस्तान की महिलाओं को बराबरी की निगाह से देखता है और उनको वे तमाम अधिकार प्राप्त हैं, जो यहां पर पुरुषों को प्राप्त हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Thank you, Sir.

Sir, my party — Communist Party of India — expresses its total support to this historic legislation. On this occasion, I would like to give my *Lal Salam* — Red Salute — to com. Gita Mukherjee, one of the outstanding Parliamentarians of our country and the galaxy of women leaders who championed the cause of women's reservation in this country.

Sir, what the august House doing today is not just giving some charity to the Indian women, but giving their due place in the decision-making bodies of the country. Sir, gender equality and women empowerment are the fundamental requirements of any society to grow into a civilized nation.

It is a Constitutional Amendment Bill. The august House is debating this Bill. I would like to remind this House what happened to the chief architect of the Indian Constitution, Dr. Ambedkar. While addressing a group of several thousands of women of depressed classes, on 18th July, 1927, Dr. Ambedkar said, "I measure the progress of community by the degree of progress which women have achieved." That is what Dr. Ambedkar said. The same Dr. Ambedkar moved the Hindu Code Bill on 11th April, 1947. The discussion on the Bill took place for several years — till 1951. Unfortunately, that revolutionary Bill could not see the light of the day. In view of the growing opposition, Shri Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister, decided to drop the Bill. Dr. Ambedkar was so disgusted that he resigned from Shri Nehru's Cabinet. While resigning, Dr. Ambedkar Said, "The Hindu Code Bill was killed and buried un-wept and unsung." Sir, the hon. Prime Minister is sitting here. I would like to tell the Prime Minister that he should not face similar fate that Shri Pandit Jawaharlal Nehru faced. Our Prime Minister, with complete support from us, will be able to pass the Bill by both the Houses of Parliament and this becomes an Act of the country very soon.

Having said this, I would like to address two issues. The first one is: I appeal to the political parties which are opposing this Bill. They are opposing on the question of reservation to OBCs or reservation within reservation. I would like to tell them that the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, the Chief of the DMK, Mr. Karunanidhi, and the hon. Chief Minister of Bihar, Mr. Nitish Kumar, have made a sensible suggestion. They said that let the Bill be passed and those issues

can be addressed at a later stage. That is the spirit that the parties which are opposing should have.

Then, Sir, I would like to address one more issue. It is the issue of reservation for SC/ST. The Bill says that rotation can take place after five years for fifteen years. The hon. Law Minister, in course of his reply, may have to address one issue and the Government will have to consider that issue in the coming days *i.e.*, amending article 334 of the Constitution which deals with reservation to SC/ST. It may appear as a challenge before the Government, because after every ten years we renew reservation. But, in order to strengthen this historic legislation, it may require some amendment to article 334. I would like to be corrected if there is any contradiction; and, legal experts must be consulted. The other issue is, I don't think this legislation is an end of all. It is just a beginning to provide space for women for their comprehensive development, for their political empowerment, for their economic empowerment, for their cultural and social empowerment. Gender equality must be the objective of the entire Parliament and the entire nation.

With these words, my party totally supports this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, among others, there are about sixteen names. Out of them, there are certain smaller parties who have given all the names of their Members. But, we would only be picking up only one, one name from each party. So, only about three minutes are possible for each Member. Now, Shri Malihabadi. You have only three minutes.

श्री अहमद सईद मलीहाबादी (पश्चिमी बंगाल): मोहतरम डिप्टी चेयरमैन साहब, आपका शुक्रिया। आज के इस तारीखी दिन में दस्तूरे हिन्द के 108वीं तरमीम के ज़रिए खवातीन रिज़र्वेशन बिल हम पास कर रहे हैं, इसके लिए हम इसका खैर मक़दम करते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि जो हमारी खवातीन हैं, क़ौमी जिन्दगी में उनका जो मुनासिब हक़ और हिस्सा है, वह उनको मिलेगा।

हमारे मुल्क में इतने बरसों से औरतों को एक मज़लूम का दर्जा हासिल था। हमने इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। दहेज के लिए औरतों को मारना, यहां तक कि माँ के पेट में जो बच्चा है, अगर वह फीमेल है, तो उसको जान का ख़तरा है। आज हम उनको रिज़र्वेशन दे रहे हैं, तो मैं यह समझता हूँ कि हमको रिज़र्वेशन की भी ज़रूरत है कि हम औरतों की जिन्दगी को बचा कर रखें। हम यह समझते हैं कि आज हिन्दुस्तान एक ऐसे सिम्ट की तरफ़ क़दम बढ़ा रहा है, जहां क़ौमी जिन्दगी का समाजी हिसाब हमारे उस हिस्से को भी मिलेगा, जिसको हम खवातीन का दर्जा देते हैं।

इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे कई ऑनरेबल मैम्बर्स ने यह बात उठाई है कि आज जो बिल हमारे सामने है, उसमें मुस्लिम खवातीन के लिए कोई हिस्सा रिज़र्व नहीं किया गया है। हम उन मैम्बर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने न सिर्फ़ पूरी मुस्लिम कमेटी को बैकवर्ड घोषित किया है, बल्कि उन्हें दलित के लैवल पर भी ला कर खड़ा कर दिया है और वह रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हो भी चुकी है एवं मंज़ूर भी हो चुकी है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमिशन ने पहली बार मुसलमानों का नाम लेकर उनके लिए 10 फीसदी रिज़र्वेशन की बात की है।

हम यह बात देखते हैं कि जब रेवड़ियां तक्रसीम करने का सवाल आता है, तो वे सिर्फ़ अपनों में ही बांट दी जाती हैं। इसमें हमें किसी से कोई भी शिकायत नहीं है कि अपनों को यह न दिया जाए, लेकिन हिस्सा सबको मिलना चाहिए। जब अक़लियतों की बात आती है, खास तौर पर जब मुस्लिम माइनॉरिटी की बात आती है, तो कुछ लोगों को यह बात पसन्द नहीं आती है। यह बात ठीक नहीं है।

یہ بیل اب پاس ہو رہا ہے اور نافیج بھی ہوگا، اعلیٰ شکتی اختیار کرے گا، لیکن ہم اس بات کی اطمینان کرتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، جو ہمارے پولیٹی سسٹم کو چلاتی ہیں، جن کے لئے ہمارے دونوں ہاؤس کونسلر ہوئے ہیں، اگر وہ انصاف کریں گی، جو زیادہ مناسیب ہوگا۔ اس طرح وہ ان تمام ترقیوں کو، چاہے وہ سٹیڈی کاسٹ ہوں، سٹیڈی ڈرائیو ہوں یا بیکورڈ ہوں، کیونکہ بیکورڈ میں سب لوگ آ جاتے ہیں، جو غریب ہیں، جو سوشل، ایکونامک اور ایجوکیشنل پیچھے ہیں، ان کا ہک دے گا۔ ہماری یہ مانگ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری سیاسی پارٹیاں اس ملک کے اندر انصاف کا سسٹم کرایم کرنا چاہتی ہیں، تو ان تمام لوگوں کو انصاف دیا جانا چاہیے، ساتھ ہی قومی زندگی میں ان کو ان کا حصہ دیا جانا چاہیے۔

مسلم خواتین کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت سی کہانیاں سنی ہیں کہ ان کے لئے بہت زیادہ جوش ہے۔ اس بارے میں مسلمان ممالک کو ایک جہت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج اس ملک کے اندر اس بات کا ٹیسٹ ہوگا کہ جو لوگ مسلمان اورتوں کو مجلوم کا درجہ دیتے ہیں، اب وہ ان کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہیں۔ ہم اپنی سیاسی پارٹیاں سے اس بات کی اطمینان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اس کے ساتھ ہی ہم اس بیل کا خیر مقررہ کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت-بہت شکریہ۔

† جناب احمد سعید ملیح آبادی (مغربی بنگال): محترم ڈپٹی چیئرمین صاحب، آپ کا شکریہ۔

آج کے اس تاریخی دن میں دستور بند کے 108 ویں ترمیم کے ذریعے خواتین ریزرویشن بل ہم پاس کر رہے ہیں، اس کے لئے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں، قومی زندگی میں ان کا جو مناسب حق اور حصہ ہے، وہ ان کو ملے گا۔ ہمارے ملک میں اتنے برسوں سے عورتوں کو ایک مظلوم کا درجہ حاصل تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ جہیز کے لئے عورتوں کو مارنا، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ فیملی ہے، تو اس کو جان کا خطرہ ہے۔ آج ہم ان کو ریزرویشن دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ریزرویشن کی بھی ضرورت ہے کہ ہم عورتوں کی زندگی کو بچا کر رکھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہندوستان ایک ایسی سمت کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں قومی زندگی کا سماجی حساب ہمارے اس حصے کو بھی ملے گا، جس کو ہم خواتین کا درجہ دیتے ہیں۔

اس سلسلے میں، میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کئی انریبل ممبرس نے یہ بات اٹھائی ہے کہ آج جو بل ہمارے سامنے ہے، اس میں مسلم خواتین کے لئے کوئی حصہ ریزرو نہیں کیا گیا ہے۔ ہم ان ممبرس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے نہ صرف پوری مسلم کمیٹی کو بیکورڈ گھوشت کیا ہے، بلکہ انہیں دلت کے لیول پر بھی لا کر کھڑا کر دیا ہے اور وہ رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش ہو بھی چکی ہے اور منظور بھی ہو چکی ہے۔ جسٹس رنگناٹھن مشرا کمیشن نے پہلی بار مسلمانوں کا نام لے کر ان کے لئے 10 فیصد ریزرویشن کی بات کی ہے۔

† [Transliteration in Urdu Script]

ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب ریوریاں تقسیم کرنے کا سوال آتا ہے، تو وہ صرف اپنے میں بانٹ دی جاتی ہے۔ اس میں ہمیں کسی سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے کہ اپنوں کو یہ نہ دیا جائے، لیکن حصہ سب کو ملنا چاہئے۔ جب اقلیتوں کی بات آتی ہے، خاص طور پر جب مسلم مائنارٹی کی بات آتی ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔

یہ بل اب پاس ہو رہا ہے اور نافذ بھی ہوگا، عملی شکل اختیار کرے گا، لیکن ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، جو ہمارے پالیٹکل سسٹم کو چلاتی ہیں، جن کے ذریعے ہمارے دونوں ہاؤس کانستٹیوٹ ہوئے ہیں، اگر وہ انصاف کریں گی، تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس طرح وہ ان تمام چیزوں کو، چاہے وہ شیڈول کاسٹ ہو، شیڈول ٹرائیس ہو یا بیک-ورڈ ہو، کیونکہ بیک-ورڈ میں سب لوگ آ جاتے ہیں، جو غریب ہیں، جو سوشلی، اکنومکلی اور ایجوکیشنلی پچھڑے ہوئے ہیں، ان کا حق دیں گے۔ ہماری یہ مانگ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری سیاسی پارٹیاں اس ملک کے اندر انصاف کا سسٹم قائم کرنا چاہتی ہیں، تو ان تمام لوگوں کو انصاف دیا جانا چاہئے، ساتھ ہی قومی زندگی میں ان کو ان کا حصہ دیا جانا چاہئے۔

مسلم خواتین کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت سی کہانیاں سنی ہیں کہ ان کے اوپر بھگتہ ظلم ہوتا ہے۔ اس بارے میں مسلمان مردوں کو ایک ظالم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج اس ملک کے اندر اس بات کا ٹیسٹ ہوگا کہ جو لوگ مسلمان عورتوں کو مظلوم کا درجہ دیتے ہیں، اب وہ ان کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہیں۔ ہم اپنی سیاسی پارٹیوں سے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اس کے ساتھ ہی ہم اس بل کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔

ڈا. (شری متی) نجمہا اے. ہپتھو (راجستھان): شکریا، ڈیپٹی چیئرمین ساہب کی آپ نے مجھے یہاں بولنے کی اجازت دی۔ کل 8 مارچ کو میرے دماغ میں تلخیوں کی طرح سے، فیلیم کی طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آج آپ جس چیئر پر بیٹے ہیں، اس چیئر سے میں نے 1996 میں اس ہاؤس میں ایک resolution move کیا تھا اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت کوئی dissent نہیں تھا۔ جب میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ महिलाओं को adequate representation یعنی سत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए तो सारे हाउस ने ही तालियाँ बजाकर उसका खैर मकदम किया था। مجھے آج थोड़ा दुःख हुआ कि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। सर، एक महिला के तौर पर मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ،

मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ,
मेरा हक है फसले बहार पर।

आज तक इस चमन में, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें अलग-अलग वर्गों और मजहबों के लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो इस अजीम हिन्दुस्तान की democracy को represent करते हैं, उसमें मुझे भी हक है कि मैं जिस जगह चाहूँ, रहूँ। चाहे मैं लोक सभा में जीत कर आना चाहूँ, चाहे राज्य सभा में रहूँ। सर, यह तो सरकार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की यह commitment है कि हम इस बिल का समर्थन करने जा रहे थे, मगर हमारी यह एक मांग थी कि जब हम बिल का समर्थन करें तो मुत्क को यह मालूम होना

चाहिए कि जो एक तब्दीली न सिर्फ लोक सभा में आ रही है, एक silent revolution, जो पंचायत बिल से हमारे देश में आया, उससे एक मिलियन महिलाएँ इस सत्ता में भागीदार हुईं। हम यह क्यों चाहते हैं? इसकी क्या वजह है? चूँकि मैं उस कमेटी की मੈम्बर थी और नाच्चीयप्पन साहब उसके चेयरमैन थे, वहाँ इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि कोई और तरीका क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, 33 परसेंट रिजर्वेशन की बात क्यों हुई, क्योंकि हमें थोड़ी सी जगह देने में तकलीफ हो रही थी। ...**(व्यवधान)**... आप तो दे देते हैं।

श्री उपसभापति: मैं दे देता हूँ?

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला: आप दे देते हैं। आपसे शिकायत नहीं है। शिकायत तो किन्हीं और लोगों से है। सर, तीन बार सुषमा स्वराज जी ने कोशिश की, मगर उस वक्त किसी ने सपोर्ट करने के लिए वहाँ से हाथ नहीं बढ़ाया। प्रधान मंत्री जी आप यहाँ बैठे हैं। आप यहाँ भी बैठते थे। आपको मालूम है कि उस वक्त भी अगर आप सपोर्ट करते तो यह बिल पास हो जाता। ...**(व्यवधान)**... अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात कही थी और जो कल मैंने प्रेस में दोहराया कि यहाँ सवाल नम्बरों का नहीं है, नम्बर तो लेफ्ट के भी थे और हमारे भी थे, सवाल नीति और नियम का था। आज हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी साफ है ...**(व्यवधान)**... सर, मैं बाहर सुन रही थी। प्रेस के बहुत से लोग बात कर रहे थे। हो सकता है कि यह बिल पास होने के बाद महिलाओं की वह importance प्रेस के लिए कल यकीनन खत्म हो जाए, मगर हमारी पार्टी के लिए खत्म नहीं होगी। सर, ये बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही थीं कि बीजेपी इसके खिलाफ है, बीजेपी इसको लाना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी ने इसमें अब discussion का अड़ंगा लगा दिया है। सर, यह बात सही है। हमारी जो चीफ व्हीप हैं, जब वह गुरु वार को गयी थीं, उसी वक्त यह तय हो गया था कि आपने इसके लिए चार घंटे तय किए हैं। इस पर discussion की मांग तो हमारी शुरू से ही थी। हम चाहते थे कि लोगों को, इस मुल्क को, इस मुल्क के बाहर के लोगों को मालूम हो कि हम क्यों इसे सपोर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते थे कि महिलाओं को आप खुद ही दिल बड़ा करके दे देते। जब आपने नहीं दिया, तब हमने यह किया।

मैं एक और बात यहां कहूँगी। हिस्ट्री है, सर। 1996 में यह रेज़ोल्यूशन यहां हाऊस में पास हुआ, फिर इलेक्शन हुए तो सबने अपने मैनिफेस्टो में बड़े जोर-शोर से लिख दिया कि महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देंगे। उस वक्त देवेगौड़ा जी जीतकर आ गए। 1997 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की कांफ्रेंस हुई, towards partnership between men and women, वहां संगमा जी ने और मैंने यह बात रखी, देवेगौड़ा जी सत्ता में थे, देवेगौड़ा जी से कहा, तो देवेगौड़ा जी ने हां भर ली, मगर बिल लाने की हिम्मत नहीं हुई। बिल आया और गीता मुखर्जी कमेटी में गया। फिर, हिस्ट्री है। सर, आज हम पंचायत की बात करते हैं, जो हमने बिल पास किया, मुझे याद है कि वह बिल रात के 12:00 बजे इसी हाऊस में तीन वोटों से डिफीट हुआ था। फिर दोबारा वह बिल लाया गया, दो-तीन साल के गैप के बाद, तब वह बिल पास हुआ। तो महिलाओं को देते वक्त थोड़ा दुख होता है। मैं समझती हूँ। वह बिल यूनेनिमस यूं पास हो गया कि कहीं हिन्दुस्तान के किसी और इलाके में एक मिलियन महिलाएँ एक मिलियन पुरुषों की सीटों पर कब्जा करने वाली थीं, मगर यहां लोक सभा में जो उंगली बटन दबा रही है, उसे यह नहीं मालूम कि कल यहां मेरी यह उंगली रहेगी या कहीं बाहर चली जाएगी। सिर्फ यही बात है और कोई बात नहीं है। सर, दुनिया में सब जगह महिलाओं का मूवमेंट है, वहां Women's movement will be led by women, लेकिन हिन्दुस्तान में, इस मुल्क की हिस्ट्री है कि हमारे जितने बड़े लोग हुए हैं, चाहे वे राजा राम मोहन राय हुए हों, चाहे ज्योति बा फूले हों, चाहे महर्षि करवे हों, चाहे बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर हों, जिन्होंने कांस्टिट्यूशन बनाया, उन लोगों ने यह काम किया। कांस्टिट्यूशन की कापी मेरे पास रखी है, चाहे आप इसके प्रिम्बल में कहें, चाहे उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहें, चाहे फंडामेंटल राइट्स में कहें, महिला को सबसे पहले वोट देने का हक जिस दिन हिन्दुस्तान के संविधान ने दिया, उसी दिन महिला को शक्ति मिल गई थी कि वह अपने प्रतिनिधि चुन सकती है और प्रतिनिधि बन सकती है। सवाल हमारा सिर्फ यह था कि किस हद तक वह महिला प्रतिनिधि बन सकती है। क्या हमारी भागीदारी

नहीं है? वृंदा जी बड़ा अच्छा बोलीं, अरुण जेटली जी ने बड़े विस्तार से इसके कांस्टिट्यूशनल और रोटेशन के बारे में जो बात बताई, मैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करूंगी, मेरी पार्टी के पास समय बहुत कम है। मैं केवल दो चीजें बाकी कहना चाहती हूँ कि आपने पॉलिटिकल इम्पावरमेंट दिया है, अभी देने की बात कर रहे हैं, दिया नहीं है। यहां से तो हम पास करके भेज देंगे। सर, आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं बार-बार कहती थी चेयरमैन साहब के चैम्बर में, गुलाम नबी जी आप भी उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे, प्रमोद महाजन से भी मैं कहती थी कि राज्य सभा में बिल लाओ, बिल पास कर देंगे, क्योंकि राज्य सभा में कोई समस्या अगर होगी भी तो थोड़ी-बहुत होगी। आज, सर, मुझे थोड़ा दुख हुआ। हमने इस हाऊस में पहली बार ऐसा सीन देखा। पिछले तीस सालों से, जब से मैं इस हाऊस की मੈम्बर हूँ, जिसमें से 17 साल मैंने उस कुर्सी पर गुजारे हैं, मुझे दुख हुआ चेयर के साथ जो बदतमीजी की गई, चेयर की शान में जो कुछ हरकतें हुईं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। चेयर के साथ जो हुआ उसके लिए सारा हाऊस मेरे साथ शामिल होगा माफी मांगने के लिए, हम सब माफी मांगते हैं। मगर, सर, चेयर का दिल बड़ा होना चाहिए, चेयर का दिल छोटा नहीं होना चाहिए। आप बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, कोई छोटे दिल के नहीं हैं। आज जिन लोगों को पकड़-पकड़ कर, उठाकर ले जाया गया, मैंने आज तक इस हाऊस में 100-150 लोगों को इस तरह हमला करते हुए नहीं देखा। मुझे खराब लगा। मैं आपसे यह बात अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि हमारे पूरे इंडिया के लोग जो देख रहे हैं, वे भी देखते हैं कि आज जो कुछ हुआ, वह डेमोक्रेसी नहीं है।

श्री तारिक अनवर: उपाय क्या है?

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: उपाय निकलते हैं, तारिक अनवर साहब, उपाय निकलते हैं।

एक माननीय सदस्य: उनको बुलाकर बात करनी चाहिए थी।

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला : हां, मैंने बताया था, बात करनी चाहिए थी, सरकार को डिस्कस करना चाहिए था, सरकार को फ्लोर मैनेजमेंट करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का हल नहीं निकलता। उनका भी हक है बोलने का। मुझे मालूम है, सर, आपके चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैंने डिप्टी चेयरमैन साहब का चेहरा देखा है, वे बहुत दुखी थे, वे मना करना चाह रहे थे। वे मना करना चाह रहे थे, अगर उनका हुक्म चलता, तो वे कभी भी ऐसा नहीं करने देते ...**(व्यवधान)**... सर, आप अपनी सीट पर बैठे थे, देखिए, प्रधान मंत्री जी भी नहीं चाह रहे थे ...**(व्यवधान)**... मुझे यकीन है कि प्रधान मंत्री जी, आपको भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को मानते हैं, हम भी जनतंत्र को मानते हैं, हम यह नहीं चाहते कि बिल सिर्फ ...**(व्यवधान)**... आपको सत्ता में भागीदारी मिल रही है, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है ...**(व्यवधान)**... यह अच्छा नहीं हुआ, कोई भी तारीफ नहीं करेगा, जो हुआ, अच्छा नहीं हुआ। आप खुश हैं, कल आपके साथ भी यह होसकता है ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति जी, हम Institution को बरबाद नहीं कर सकते, Institution को कायम रखना हमारा फर्ज है। सबसे पहले उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए था, उन्हें एक हद तक ही बोलना चाहिए था। उन्हें अपनी बात बोलने का हक है, चिल्लाने-चीखने और तोड़-फोड़ करने का अधिकार उन्हें नहीं है। मैं उनके बर्ताव को कंडम करती हूँ, लेकिन हमें भी दिल बड़ा रखना चाहिए। आज अगर वे भी यहां आकर बोलते, वे आकर अपना dissent बताते कि क्या problem है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नजमा जी, अब आप समाप्त कीजिए।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला: सर, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी पार्टी का समय अभी बाकी है। आप क्यों दिल छोटा कर रहे हैं, मैं दिल बड़ा करने की बात कर रही हूँ। मेरा तो चिल्ला-चिल्लाकर गला दुख गया। मैं इस दुःख के साथ इस बिल का पूरा समर्थन करती हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि यह बिल आया और हमारी पूरी पार्टी इस बिल के ऊपर आपके साथ है, महिलाओं के साथ है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा काम

कर रहे हैं, जो हम भी करना चाहते थे, ये कह रहे हैं कि आपने उस समय हमारा साथ नहीं दिया ...**(व्यवधान)**... लेकिन आज हम आपका साथ दे रहे हैं, आपके पास मैजोरिटी नहीं है, फिर भी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उपसभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उपसभापति जी, मैं इस महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में बहुत खुशी से अपनी ओर से, सदन की सभी महिलाओं की ओर से, हमारे तमाम उन भाइयों की ओर से जो इस बिल को समर्थन दे रहे हैं, पूरे देश की जनता की ओर से, जिसमें स्त्रियां और पुरुष दोनों शामिल हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस ऐतिहासिक बिल के संबंध में अपने कुछ विचार आज यहां रख रही हूं।

उपसभापति जी, आज जब यह विधेयक यहां पारित होने जा रहा है, तब इस अवसर पर मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी का स्मरण किए बिना नहीं रह सकती। यह उनकी परिकल्पना थी। वे स्वयं पुरुष थे, लेकिन उनके मन में महिलाओं के प्रति करुणा थी और उन्होंने महसूस किया कि इस देश की स्त्रियों को राजनीतिक हक और राजनीतिक अधिकार तब तक नहीं मिल सकता, जब तक कि आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो जाती। उनकी इसी सोच के तहत कांग्रेस सरकार के समय में पंचायतों में हमारी बहनों को 33 फीसदी आरक्षण मिला, नगर निगमों और निकायों में भी हमारी बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण मिला। मेरी बहन नजमा जी अभी कह रही थी कि राजीव जी की सरकार के समय में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था और केवल 2 वोटों से गिर गया था, मैं उनसे सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि उस समय कौन लोग थे, जो इसका विरोध कर रहे थे और वे किस तरफ थीं, किन लोगों के विरोध के कारण उस समय यह विधेयक गिरा था? आज खुशी की बात है कि देर आयद दुरुस्त आयद, आप लोगों ने यह महसूस किया कि महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना, महिलाओं को समर्थन दिए बिना, आपका आपके घर में भी गुजारा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनकी इच्छा शक्ति को, UPA सरकार को और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने परमाणु करार जैसी दृढ़ता दिखाई। अगर वे इतनी दृढ़ता नहीं दिखाते, इतनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाते, तो मैं नहीं समझाती कि किसी भी सरकार के समय में यह ऐतिहासिक आरक्षण विधेयक इस संसद का मुंह तक देख पाता और पारित हो पाता। लोग तो देख नहीं पाते हैं, बहुत कुछ बातें करते हैं, मगर जनता सब जानती है और मीडिया भी सब समझता है। असलियत सब जानते हैं और जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं भी ओबीसी समाज से आती हूं। राज्य सभा में मेरी पार्टी ने मुझे लिया, किसी पूंजीपति को नहीं लिया। जो उधर बैठ कर बातें करते हैं, उनमें से कितने कमजोर लोगों को राज्य सभा में लेकर आए, कितनी मुस्लिम समाज की हमारी बहनों को, कितनी ओबीसी समाज की हमारी बहनों को लेकर आए? उस समय उन्हें बड़े नामी-गिरामी लोग, बड़ी हस्तियां या बड़े पूंजीपति लोग याद आते हैं। जो इस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ कर कहना चाहती हूं कि देश की बहनों और इस समाज को गुमराह मत कीजिए। आप चाहें तो 33 प्रतिशत से ज्यादा ओबीसी की बहनों को टिकट दे सकते हैं, Minorities की मुस्लिम समाज की बहनों को टिकट दे सकते हैं। जब यह विधेयक पारित होगा, तब देश की बहनें देखेंगी कि आखिर आपकी कितनी इच्छा शक्ति है। कितने मुस्लिम समाज की बहनों को और कितनी ओबीसी समाज की बहनों को आप उस समय टिकट देते हैं। उस समय यह मत कीजिएगा कि उन समाजों के नाम पर अपने ही घर की बहन, बेटियां, बहू और बीवी नजर आए। उस समय यह जरूर देख लीजिएगा। इस पर भी देश की नजर रहेगी। मैं इस सरकार को बधाई देते हुए अंत में यही कहना चाहती हूं कि जिन सबने ने समर्थन दिया है **..(व्यवधान)..** कल जो यहां पर हंगामा हुआ, जिस तरह से सभापति जी के आसन का अपमान किया गया, हम उसका तहे दिल से निंदा करते हैं। उसके खिलाफ यदि कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो भविष्य में भी राज्य सभा जैसे सदन में इस तरह के उत्पात होते रहेंगे। आगे भविष्य के लिए अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। हमारे साथियों द्वारा यह कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया, तब यह कार्रवाई की गई। हम निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में कोई

अपना विरोध प्रकट करने के लिए इस हद तक अनुशासनहीनता नहीं करेगा और हम सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। मैं महिला शक्ति को नमन करते हुए, पूरी देश की महिलाओं को नमन करते हुए, श्रीमती सोनिया जी को नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि

*“हम उबलते हैं, तो भूचाल उबल जाते हैं,
हम मचलते हैं, तूफान मचल जाते हैं।
हमको कोशिश न रोकने की करे अब कोई,
हम जो चलते हैं, तो इतिहास बदल जाते हैं।”*

अब यह नया इतिहास इस देश में आज यूपीए सरकार ने बनाया है। यह प्रधान मंत्री जी की देन है, यह कांग्रेस नीत सरकार की देन है। यह बात पूरा देश जानता है और आप भी जानते हैं। जो पचास फीसदी की बात कह रहे थे, उनसे कहना है कि साथियो, हमारी सरकार पंचायतों और नगर निगमों में आरक्षण को 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी तक ले गई है और एक बार फिर प्रक्रिया शुरू हुई है, अब देखिए, आगे, आगे होता है क्या। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri M.V. Mysura Reddy; you have three minutes. SHRI

M.V. MYSURA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak on behalf of the Telugu Desam Party. I am proud to take part in this historic debate. There is no doubt that empowering of women will work as an indispensable tool for eliminating gender inequality and discrimination. Mahatma Gandhi had rightly said, “Man’s education is education for himself; woman’s education is education for the society. I strongly feel that empowerment of woman is not only empowering herself but also empowering the society.” Our Party totally, wholeheartedly supports the Constitution Amendment Bill, and it is not out of way to mention that it is the Telugu Desam Party which had first implemented reservation for women in local bodies and N.T.R. was also the first Chief Minister of Andhra Pradesh who had given property rights to women in 1986. I want to bring it to the notice of this august House that our Party is committed to reservation for backward-classes women and for the minority community also. If the Government comes forward with official amendment also, our Party will support that official amendment. Our Party wholeheartedly supports this Constitution Amendment Bill. Thank you.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभापति जी, मुझे याद है आज से 22 साल पहले पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में गांव-गांव तक मजबूती के साथ उभरकर आएँ, इसकी पहल की गई थी और बाद में 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर केंद्र सरकार ने पंचायती राज में एक-तिहाई महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी। उस वक्त यह एक क्रांतिकारी पहल थी और इसके माध्यम से महिलाओं का एक नया स्वरूप राजनीति में उभरकर सामने आया। बिहार सरकार ने इसके अच्छे परिणामों के कारण पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया और इसका अनुसरण अन्य प्रदेशों ने भी किया, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और गुजरात की राज्य सरकारें शामिल हैं। इस आरक्षण के कारण ही गांवों के स्तर पर एक ओर तो महिलाओं में उम्मीद से ज्यादा जागरूकता पैदा हुई, दूसरी ओर पढ़ी-लिखी और अनपढ़, दोनों ही तरह की महिलाओं की नेतृत्व क्षमता भी सामने उभरकर आई। यह महिलाओं की इच्छाशक्ति और लगनशीलता का प्रतीक है कि आज गांवों में महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारी का बखूबी से निर्वहन कर रही हैं। वे घर के चौके-चूल्हे से लेकर प्रदेश के विकास में भी हाथ बंटा रही हैं।

उपसभापति जी, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पंचायतों के, स्वायत्त संस्थाओं के जो नगरीय चुनाव हुए हैं, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण गांवों में और शहरों में विकास की बागडोर 2,00,000 से ज्यादा महिलाओं के हाथ में आई है। वहां 1,80,000 से ज्यादा महिलाएं पंच बनी हैं, 11,520 महिलाएं सरपंच बनी हैं, 3,400 महिलाएं जनपद की सदस्य बनी हैं, 415 महिलाएं जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, 25 महिलाएं जिला पंचायत महिला अध्यक्ष बनी हैं, 1,780 महिलाएं पार्षद चुनकर आई हैं और हमारे यहां 8 महिलाएं नगर निगम की महापौर बनी हैं, जिसमें भोपाल में सामान्य महिला की जो सीट आरक्षित थी, उस पर ओ.बी.सी. की महिला महापौर चुनकर आई है। ये आंकड़े बताते हैं कि यह कितना क्रांतिकारी बदलाव है।

उपसभापति जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो सर्वप्रथम विधान सभा और संसद में महिलाओं की 33 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत बड़ौदा राष्ट्रीय परिषद में जून, 1994 में प्रस्ताव पास करके की। महोदय, उस समय महिलाओं को यह जानकारी भी नहीं थी कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए इस तरीके का कोई प्रस्ताव हमारी पार्टी पास करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए यह प्रस्ताव पास किया और इसके बाद हमारी पार्टी ने संगठन में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देकर राजनीति में आगे बढ़ाने का काम पहले से ही शुरू कर दिया। मुझे याद है कि एन.डी.ए. के कार्यकाल में दो बार पूर्व प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विधेयक को पास कराने के लिए आम सहमति बनाने के प्रयास किए और सुषमा स्वराज जी, जो उस समय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर थीं, उन्होंने इसके लिए बेहद परिश्रम किया और इसे संसद में चर्चा के लिए रखा, पर उस वक्त हमें सफलता नहीं मिली। महोदय, इस महिला आरक्षण विधेयक का मेरी पार्टी समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में आरक्षण देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में निर्णायक भूमिका देने की पक्षधर रही है। हम कोई राजनैतिक खेल खेलना नहीं चाहते और न ही श्रेय लेने की होड़ में इस विधेयक में रोड़ा डालना या अवरोध पैदा करना चाहते हैं, जो दल विरोध कर रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन और सुधार की गुंजाइश हमेशा हो सकती है। संसद में बहस के दौरान सभी दल अपनी भावनाओं और विचारों को रखते हुए विधेयक में उसे समाहित करने का प्रयास करें। लेकिन मेरा यह भी आग्रह है कि इस विधेयक को उसके वर्तमान स्वरूप में ही पास कराया जाए। आने वाले समय में अनुभव के आधार पर विधेयक में संशोधन और परिमार्जन किए जाने की संभावना सर्वथा बनी रहेगी। उपसभापति महोदय, पिछले कई वर्षों से संसद में महिला आरक्षण विधेयक लम्बित रहने से आम जनता में यह संदेश जा रहा है कि हमारी संसद महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि इसी संसद ने महिलाओं के हितों और अधिकारों की रक्षा तथा उनकी तरक्की के लिए कई कानून बनाए हैं। इसीलिए मेरी सबसे यह अपील है, मैं सबसे यह आग्रह करना चाहती हूँ कि सब इस विधेयक के प्रति उदार भाव रखें ताकि इसके पारित होने की सूरत उभर सके। महोदय, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस विधेयक की पक्षधर रही है। आज, जब सदन में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है और इस पर मैं अपनी बात रख रही हूँ तो इस विधेयक पर अपने विचार रखते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। लेकिन दो दिन का जो घटनाक्रम था, उसने जो पीड़ा पहुंचाई है, अगर हम पहले से इसका थोड़ा सा होमवर्क कर लेते तो शायद ऐसी कटुतापूर्ण स्थिति न आती और हमें उन भाइयों का, उन दलों का समर्थन भी मिलता, या उनकी सहमति भी हो सकती। ...**(समय की घंटी)**... एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम आज इस विधेयक का जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं...

श्री उपसभापति: माया सिंह जी, अभी आपकी पार्टी से एक और मेंबर बोलने वाले हैं।

श्रीमती माया सिंह: मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भी ऐसी ही जिम्मेदारी का परिचय देकर इस विधेयक का समर्थन करती तो एनडीए के शासनकाल में ही यह विधेयक पारित हो गया होता और इसका लाभ हमारे देश की महिलाएं ले रही होतीं। यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की

दिशा में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है, जो हमारे संविधान निर्माताओं के उस सपने को मूर्त रूप देगा, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में गैर-बराबरी को मिटाने की हसरत रखता था। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय समाज में महिलाएं किस तरीके से अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और दूसरी नागरिकता का शिकार रही हैं। ...**(समय की घंटी)**... संसद के भीतर और बाहर महिलाओं के हितों और अधिकारों की रक्षा के जो भी प्रयास हुए हैं, उनमें से महिला आरक्षण विधेयक एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा जो उन्हें राजनैतिक और शासन चलाने की प्रक्रिया में अधिकार सम्पन्नता के साथ सबद्ध करता है। दुनिया भर में चल रहे नारी मुक्ति आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलनों से भी आगे बढ़कर यह महिलाओं को अधिकार देगा। सर, आजाद भारत के इतिहास में महिलाओं को मजबूत करने का, महिलाओं के सशक्तिकरण का हमारा इतिहास रहा है। आज जब संसद में महिलाओं को यह कानूनी अधिकार मिलने जा रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक प्रसंग की मूक गवाह नहीं है, बल्कि इसकी सक्रिय भागीदार बनने जा रही है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस महिला आरक्षण विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूँ और अन्य दलों से अपेक्षा करती हूँ तथा उनसे आग्रह करती हूँ कि वे भी इस विधेयक का समर्थन करें ताकि यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. (SHRIMATI) KAPILA VATSYAYAN (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise here on behalf of the nominated Members of the Rajya Sabha. We belong to no parties but we belong to the human race. At this momentous moment, all that I can say is to remind this House of one sentence of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, writing to Julian Huxley in 1946 when UNESCO was started. What did he say? He said, I learnt from my illiterate but wise mother, that all rights to be deserved and preserved came from duty well done. Today, I think whether illiterate mothers or literate mothers, they will have to bring about a civilised society; a civilised society which cannot, in the very nature, indulge in the kind of action that we saw yesterday.

With these words, Sir, I say this is a momentous moment, but it will be for us to show in action what we have shown in this legislation. Thank you, Mr. Deputy Chairman.

सरदार तरलोचन सिंह (हरियाणा): शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन साहब, आज इस हाउस को यह श्रेय जाता है कि हम यह हिस्टोरिक बिल पास करने जा रहे हैं। अभी किसी सदस्य ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इस बिल की हिस्ट्री यह है कि 1997 में जब श्री इन्द्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, तो पहली बार यह बिल लाया गया, दो बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लाए, लेकिन पास नहीं हुआ। अब जब इस हाउस में आया तो एक कमेटी बनाई गई, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर दो साल काम किया, जिसका श्रेय इस कमेटी को जाता है। इस कमेटी के पहले चेयरमैन श्री नाच्चीयप्पन थे और फिर श्रीमती जयन्ती नटराजन चेयरमैन बनीं। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। इस कमेटी ने पूरे देश में जाकर अध्ययन किया और आज यह बिल आया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी और लीडर ऑफ दि अपोजिशन को कि आज हमारा हाउस इस बिल को पास करने जा रहा है, इसलिए ये दोनों बधाई के पात्र हैं। हम सारे लोग इकट्ठे होकर इसको आज पास कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने 540 साल पहले हिन्दुस्तान में यह जो सोशल रिवोल्यूशन जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि:

“क्यों मन्दा आखिए जित जम्मे राजान”

वह लेडी जो किंग सेंट को पैदा करती है, वही सबसे ज्यादा सम्मान की पात्र है। मुझे खुशी है कि आज गुरु नानक देव जी के उपासक डा० मनमोहन सिंह आज इस बिल को पास करवा रहे हैं। मैं ज्यादा बातें न

कहता हुआ, क्योंकि समय कम है, पंजाब और हरियाणा में यह बिल अमली तौर पर ऑलरेडि अपने मन से किया हुआ है। पंजाब में लोक सभा की 13 सीटों में से चार वूमेन इलेक्ट हुईं, जिसमें 33 परसेंट हो जाता है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिसमें दो वूमेन इलेक्ट हुईं। तो ऑलरेडि पंजाब और हरियाणा इसकी तरफ चल रहा है। हरियाणा की कल्पना चावला astronaut भी बनी। तो औरतों के प्रति सम्मान में हमारे यहां कोई कमी नहीं है। चौधरी देवी लाल को श्रेय जाता है कि सबसे यंगेस्ट सुषमा स्वराज जी को मंत्री बनाया। आज सुषमा स्वराज जी जिस सीट पर बैठी हैं उसका श्रेय चौधरी देवी लाल को जाता है। मैं यह ही नहीं, यह भी कहना चाहता हूं कि इस बिल में जब कमेटी ने काम किया तो कई सझाव आए। इसमें यह सुझाव भी आया कि सीटें बढ़ाओ और डबल सीटें करो। यह भी सझाव आया कि अपोजिशन पार्टी को यह मांग करो। लेकिन एक सझाव यह भी आया कि जो आज डिमांड ओ0बी0सी0 के बारे में है, इसको आप स्टेट्स को दे दें। जैसे पंचायती राज में हर स्टेट को पॉवर है और अगर वह चाहे तो ओ0बी0सी0 की सीटें कर सकता है। तो इस बिल में भी यह प्रोविजन हो सकता है, तो यह किया जाए। महोदय, मैं एक और बात बिना कहे नहीं रह सकता हूं। जब आज लेडीज के नाम पर हम सब कार्य कर रहे हैं तो प्रधान मंत्री जी, सिख लेडीज की छोटी सी बात पेंडिंग पड़ी हुई है। मझे खुशी है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने तथा पिछले लॉ मिनिस्टर साहब ने भी प्रोमिस किया था कि आनन्द मैरिज एक्ट जिसमें सिखों की मैरिज होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन क्लॉज नहीं है। इतनी छोटी सी मांग जो मैं यहां तीन साल से पेश कर रहा हूं, पूरी नहीं हुई है। इस बारे में तमाम सिख मेंबर पार्लियामेंट ने भी कहा है, आज लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उसका भी आज यहां वूमेन डे पर ऐलान कर दो, ताकि सिख लेडीज भी आपका धन्यवाद करें। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, voting will be around six of the clock.

SHRI MANOHAR JOSHI (Maharashtra): Sir, the Bill for consideration before the House is really an important one. I must remind the House that the same Bill came up in the Lok Sabha in 1996. When the debate started in that House, I remember, the Maharashtra Assembly had passed unanimously a resolution which was moved by me as the Chief Minister and that resolution said that Women Reservation Bill should be supported not only by the State of Maharashtra, by all the Assemblies in the country. And, therefore, I must make it clear that this Bill is accepted by my party for a long time, that is, since 1996. Therefore, there was no question before us whether we should support the Bill or we should oppose the Bill.

Sir, I remember that whenever this Bill came up in Parliament for discussion, my party chief, Shri Balasaheb Thakre, had always asked us to vote in favour of the Bill. The only demand right from the beginning from my party was that particular constituencies should not be reserved for women. We wanted, as the Leader of Opposition has already said, the reservation of constituency for women should be decided by all political parties. Every party should decide and the mandate should be given by the Parliament that whichever party contests the elections, either of Lok Sabha or Legislative Assembly, 33 per cent of the contestants should be women. And, this was the point for which we had requested different authorities in the Government saying that the experience of reserving particular constituencies is not good because the candidates who contest election are not sure whether next time their constituency will be reserved or not. Therefore, in the larger interest of the people in the constituency, I would still request the hon. Prime Minister because I have spoken to a number of political parties and they

also have expectation that the reservation of 33 per cent should be done by the political parties themselves. Except that, I always thought that by passing this Bill, we will be looking into the interests of our own mother, sister and wife. (*Time-bellings*) Passing this Bill means bringing happiness not only in the constituency but also in your family. And, therefore, Shiv Sena strongly supports the Bill before the House and we expect that after passing of the Bill, the women in the country also start taking keen interest in politics and do the social work as much as possible.

Sir, with these few words, I express the opinion of my party that the entire House should unanimously pass this Bill and also try to find out a way whereby the constituencies will be decided by the parties themselves. Thank you very much.

श्री राज मोहिन्द्र सिंह मजीठा (पंजाब) : ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आज हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में एक हिस्टोरिकल बिल पेश हुआ है, उस पर आपने मुझे बोलने का टाइम दिया है। भारतवर्ष में औरतों की आबादी तकरीबन आधी या 48 परसेंट है। हजारों सालों से औरतों पर जुल्म होते आए हैं। सबसे पहले औरतों के हक में जिसने आवाज उठाई थी, तो वह सिख कौम थी और बाबा गुरु नानक जी थे। 1526 में जब बाबर ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था, तब बाबा नानक जी उस समय ऐमनाबाद में घूम रहे थे। जिस तरह आतताइयों ने अपनी बिरादरी को भी नहीं छोड़ा, उस बारे में बाबा नानक जी ने बहुत कुछ कहा है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरी पार्टी व शिरोमणि अकाली दल के प्रधान की इच्छा के मुताबिक, मैं और मेरे साथी गुजराल साहब और बाजवा जी इस बिल का सपोर्ट करते हैं। शिरोमणि अकाली दल एक ऐसी जमात है कि इसने औरतों के बारे में काफी कुछ किया है। यह SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़ी कुरबानियों के बाद बनी। इसको महात्मा गांधी जी, पं० जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सपोर्ट किया। उसका इलैक्शन पिछले सालों में हुआ है और हमारे प्रधान सरदार बादल जी ने 40 परसेंट औरतों को टिकट देकर खड़ा किया और वे कामयाब हुए। ऐसे ही पंजाब में चाहे वह किसी भी पार्टी में है, उनके दिमाग में औरतों के बारे में जो इज्जत है, वह और किसी और सूबे में कम होगी। पिछली पार्लियामेंट में 13 में से 4 औरतें जिनकी संख्या 33 परसेंट के करीब बन जाती है, वे हमने भेजी हैं। 50 परसेंट अकाली दल की महिलाएं, इस हाउस की मैम्बर्स बनी हैं। यह ठीक है कि आज इस बिल को प्रधान मंत्री जी की पार्टी ने पेश किया है। इस बिल को पहले भी दो प्राइम मिनिस्टर्स ने पेश किया है। इसका क्रेडिट उनको भी जाता है। पहले 11वीं लोक सभा में गुजराल साहब जी ने और फिर अटल बिहारी वाजपयी जी ने दो दफा पेश करने की कोशिश की है। हमारी पार्टी NDA का हिस्सा है और BJP तथा अकाली दल वाले इस बिल को पास करवाने के लिए कोशिश करेंगे।

(उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए)

*Ambika Soni ji, please listen to me carefully. I want to speak on the amendment on the basis of my experiences in Punjab.

Panchayati Raj was started in Punjab and women were elected as sarpanches as a result of 33% reservation. When one goes to get some signatures the husbands of the women sarpanches claim themselves to be the real sarpanches; I dread the same here and hope we don't bring illiterate women here and allow their husbands to claim themselves as Members of Parliament. Dear sister I request that matriculation should be the minimum qualification to become a member so that the women understand what they are reading and somebody doesnot compel them to write what they are not aware of.

*English Translation of the original speech in Punjabi

With these words I congratulate the Prime Minister who is from Amritsar.

WAHE GURU JI KA KHALSA
WAHE GURU JI KI FATHEH !!

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Thank you, Sir. I rise here to support this historic Bill on behalf of the DMK and my leader, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, who has unflinchingly supported this Bill, who has always stood by the women of this country, and the UPA-II, to make sure and see that it is passed.

Sir, I would like to recollect the words of our social reformer and thinker Periyar who once said that the women of this country are suppressed, are the outcasts and *dalits* of this country, in spite of whichever religion they belong to, whichever community they belong to or whichever caste they belong to. Today, this is an opportunity for us to make right the historical mistakes, the crimes which we have committed against the women of this country.

Sir, we have passed so many Bills. We have made so many amendments. There have been many laws made in this House, in the Parliament and in the State Assemblies. Many Budgets have been passed without hearing the voice, without listening to the opinions of half of the population of this country! Does the price rise not affect us? Does the climate change not affect us? But nobody hears us. Had there been an opportunity awarded to the women of this country to say what they want, the situation would have been quite a different one. Does the allotment of money to education or anything affect the women? Our opinions have not been heard; we have been ignored for many years in this country. Today, I congratulate the UPA Government, the UPA Chairperson Mrs. Sonia Gandhi, our Prime Minister, our President and every political party and leader, who have stood by us and supported this Bill. Yesterday, we started with euphoria; we were all so happy and we were really looking for the day when this Bill was going to be passed. But, unfortunately, we went back with heavy hearts. There were differences of opinion, but Members started blaming each other. We were all worried. But I am proud to say that we have all come back together to pass a Bill which we all believe in. I once again congratulate every leader in this House, every Member in this House, all those who have come together to pass this Bill.

Sir, there are a lot of questions raised about this Bill. A few days ago, our leader Dr. Kalaignar issued a statement, and in that statement, he had quoted Rousseau. In his statement, Dr. Kalaignar said:

“The ‘general will’ reflects the welfare of the overall group, without taking into account the conflicting interests of this constituents. This must not be misunderstood as a suppression of constituent viewpoints, but as a means to execute and implement the common interests of a group initially. Once the execution is carried out, it is important that the ‘general will’ always be open to challenge and questioning.”

So, today, people are talking about reservations within reservation. They were worried about minorities, and I am sure the Government, I am sure all of us who are interested in protecting the interests of the OBCs, and also the interests of the suppressed classes and the minorities, will make sure that the amendments are passed later like what we have done in Tamil Nadu. We had the SC reservations and we realized that a small community, the Arunthathiyar community, within that category, needed more protection, needed more help. So, we have made an exclusive three percent reservation for the Arunthathiyar community. Likewise, we can make changes; we can amend this Bill later. So, I request everybody to let this Bill be passed. Today is a historic day. It is a dream coming true. Especially our Poet Bharathi said:

(Hon. Member spoke in Tamil)

Today is the day that we should see that this really happens. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you very much, Shrimati Kanimozhi. Now, Shri Pyarimohan Mohapatra.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Orissa): Sir, I rise to support this Bill and I congratulate the Prime Minister and pay tributes to all his three predecessors, Shri Vajpayee, Shri Gujral and Shri Deve Gowda, who had tried to bring the Bill and been frustrated. I congratulate the Leader of the Opposition, the leaders of all political parties, including the Left Parties, and all those who have unequivocally supported you in getting this Bill passed. Please don't keep on harping that so and so has done it. You couldn't pass this Bill on your own strength. Please give everyone his due. That is my plea.

It is unfortunate that in this House the disciples of late Ram Manohar Lohia did create some unfortunate scenes forgetting what Ram Manohar Lohia stood for. He stood for amelioration of the condition, torture of women. He thought women in India, irrespective of caste and class, were tortured, exploited and demeaned by men and, therefore, he wanted some kind of representation by reservation for women of all castes and classes. The Biju Janata Dal, my party, which was named after our great leader, late Biju Patnaik, has deep commitment to the empowerment of women and representation of women in the State Legislatures and at the Centre. Bijubabu, when he was the Chief Minister, said that men had not succeeded in solving the problems of the country and, therefore, the time had come that women should come forward and they should be entrusted with the responsibility of taking the leadership. He reserved one-third of the seats for women in the panchayat raj institutions and urban local bodies well before the Constitution Amendment was made. We have 30 per cent reservation for women in jobs. It is compulsory to put the name of the mother. We did it long before the AIADMK did it in Tamil Nadu. That was done in 1991. While admitting the children to schools, it is compulsory to put the name of the mother. The name of the father is optional. Joint recording of Pattas is compulsory so that the assets would be available to the women also. His son, the present Chief Minister and President of the BJD, Shri Navin Patnaik, has taken women empowerment to new heights. In

the International Women's Year in 2002, he nominated two women Members to the Rajya Sabha. We had one-third Members here. We have, an OBC lady Member, here. You are talking about OBCs and Muslims and saying that we are not taking care of them. We are committed to 50 per cent reservation. Bijubabu, when he was the Chief Minister, in a meeting in the Parliament House Annexe, had demanded 50 per cent reservation.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, Mr. Mohapatra, please conclude.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, I will take one more minute, please. We have made 50 lakh for women as members of Self Help Groups for empowering them. We have created a number of things.

Sir, for lack of time, I am concluding. In spite of a number of weaknesses in the Bill like rotation system and non-inclusion of OBCs, we support this Bill. All the other things can be taken care of later through discussions and deliberations. My party has abiding faith in woman power and their ability to shape the destiny of the country for the better. Therefore, we support the Bill and we will support any amendment which will be brought forward in future to better the condition of women in this country. Thank you.

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I would like to quote the words of Mahatma Gandhi who said, "Man the law-giver will have to pay a dreadful penalty for the degradation he has imposed upon the so-called weaker sex. When woman, freed from man's snares, rises to the full height and rebels against man's legislation and institutions designed by him, her rebellion, no doubt, non-violent, will be none the less effective."

The words of the father of the nation are finally coming alive today in this historic Session of the Indian Parliament. The implication of the Women's Reservation Bill, which recognises the perpetuating inequalities of the sexes and seeks to empower the fairer sex by reserving one-third of the seats in State Legislatures and the Parliament, is indeed a rebellion in some sense against the age-old institutions that have continued to alienate women from politics since the very foundations of democratic institutions were set.

The progressive efforts to make a legal provision for reserving seats for women in State Legislatures and the Parliament came into being during the term of Shri Rajiv Gandhi, as Prime Minister, with the Panchayati Raj Act of 1992. Thereafter, it was Shri I.K. Gujral, who during his Prime Ministerial tenure, personally, piloted the Bill and presented it in the present form in the 11th Lok Sabha. Unfortunately, due to opposition from various quarters and lack of support, the Bill could not be passed. Shri Atal Bihari Vajpayee, as Prime Minister, made two attempts to get this Bill passed, but to no avail.

Sir, it is commendable that today almost all political parties are unanimous in their support of this groundbreaking Bill — a far cry from the Parliamentary proceedings of 1997. This is a true reflection of the fact that the Indian people, as well as their elected representatives, are far more sensitive to the rights and aspirations of the Indian women.

Regrettably, however, I must point out that there has been a lot of * on the part of certain party leaders who are today pretending to be the champions of democracy.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The word * used by you is unparliamentary. Therefore, that word is deleted.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, I withdraw that word. They could easily have given tickets to more women from their parties in the last 13 years. They chose not to do so. However, this law will now force their hand and women will finally find their rightful place under the sun, despite the inactions that have marked the history of this Bill.

Sir, allegations are being made by some political leaders....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Three minutes are over. Please conclude.

SHRI NARESH GUJRAL: With these words, on behalf of my party,

I support the Bill.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very proud to associate myself with this historic event. I remember, in the year, 1996, for the first time, this Bill was moved during the tenure of the United Front Government. In 1996, myself and my party, totally, supported the Bill. Today again, I am standing here, on behalf of my Party, the Asom Gana Parishad, to support this Bill. Although I strongly support the Bill, yet I must point out that it was initially not done in a proper manner, and this could have been avoided.

Sir, we are here today to pass the Constitution (Amendment) Bill, and I am very sorry about the unwanted situation that happened today. This could have been avoided. Sir, I am coming from the North-Eastern Region of our country where the composition of women is very high. It is known to everybody that in the name of dowry, many women get killed every day in many parts of our country. But this situation is not applicable to Assam and other North-Eastern Region of our country. This is the position of women in our society. Now I recall the role of the women of Assam in the success of the Assam Movement. My Party, the Asom Gana Parishad, was formed after the successful ending of the Assam Movement against the foreign nationals in Assam. I recall that lakhs of Assamese women took part in the struggle; there were a lot of agitations carried out by the Assam Movement. Today, on behalf of my party and on behalf of the people of Assam, I would like to salute the women of Assam who took

*Expunged as ordered by the Chair.

part in the Assam Movement. After the successful ending of the Assam Movement, the Assam Accord was signed, and our party, the Asom Gana Parishad, was formed. Today, I am standing here to declare our full support to the Women's Reservation Bill moved by the Government. Thank you, Sir.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Sir, I rise to speak on behalf of Swatantra Bharat Paksh. The position of my party can be very briefly summarised as follows: Political empowerment for women — a “thumping yes, yes, yes.” Reservation — a fairly big question mark. And, Rotation and lottery system — “An absolute No, No, No.” It was in 1986 that the Shetakari Mahila Aghadi of my party, the Rural Women's Organisation in Maharashtra, decided for the first time to have 100 per cent women's panel for contesting the Panchayati Raj elections. It was the Congress (I) Party, under Shri Shankar Lal Chauhan in Maharashtra, who opposed that idea and postponed all elections to the Panchayati Raj for three years running. And it was only after that that they accepted the concept of 33 per cent reservation. Sir, hon. Mishra of the BSP raised the question: Where does this reservation come from? This is the genesis of 33 per cent. Now, the question is: Has the reservation, actually, ever given benefit to any of the targeted communities? And our experience is not very happy. This problem could have easily been solved by a system of proportional representation rather than the Party List system. That would take care of the entire set of problems connected with reservation. And, the scenes that we have witnessed in the last two days could have also been avoided had we included proportional representation instead of the Party List system.

Lastly, coming to the lottery-cum-rotation system, this is not a minor defect. I still insist that this is a fatal defect in the system. Here, we choose a constituency first, and it is very likely that for that constituency, there may not be an enthusiastic woman candidate. On the other hand, it is likely that a man has nursed that constituency for some time. This will unnecessarily create bitterness against the women's movement. Sir, secondly, it is also likely that this opportunity will be used by established leaders for pushing the candidature of their family members which is not the purpose of this Bill at all. Sir, once a woman is elected, she would know that she does not stand a chance of getting the ‘woman reserved constituency’ again. Therefore, she would not be equally enthusiastic about nursing the constituency. Similarly, the men candidates who get elected would also have doubts about their getting to contest that election once again from the constituency because the chances that it will be available to them would be only 50:50. Under these circumstances, Sir, the major effect will be that all the constituencies will be badly nursed.

And, lastly, Sir, this kind of a reservation system will make it impossible for any House to have more than 33 per cent repeaters at any time. So, we will lack the experienced people in the Legislatures and the Parliament. That could prove to be fatal for the Indian Democracy. Thank you, Sir.

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश): शुक्रिया। पिछले दो दिनों से जो कुछ हाऊस में मैंने देखा, इससे बड़ा दुख भी है, अफसोस भी है। इसको बयान करने का इजहार मैं इस शेर के साथ करना चाहता हूँ :—

रंगो गुल का है न सलीका, न बहारों का शअुर
हाय किन हाथों की तकदीर में तकरीरे हिना ठहरी।

हालत यह है कि जो कुछ हमने देखा, बहुत अफसोसनाक है, लेकिन इस बात की भी एक खुशी हो रही है कि हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ लीडरान ने यह फैसला किया कि हम देहात और खलिहानों से औरतों को लाएंगे और हिन्दुस्तान के उस सबसे बड़े मंदिर में, जहां कानून बनाए जाते हैं, वहां लाकर इम्पारमेंट देंगे। यह एक अलग बात है कि वहां की औरतें आज रोज़ डॉवरी की शिकार हो रही हैं, उधर हमारी तवज्जो नहीं है, वहां की औरतों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तालीम नहीं मिल रही है, लेकिन हम पार्लियामेंट में उनको लाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जब सबकी यह राय है तो मेरी भी यह राय है। मेरे दिल की जो कैफियत है, वह उधर बैठे तिवारी जी ने बयान की है। मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के लिए एक तश्वीश का लम्हा आ गया है। यह वह वक्त है, मैंने देखा है पार्लियामेंट के और असैम्बली के इलेक्शनों में, तरीकेदार यह है कि अगर तीन लाख ठाकुर हैं और चार लाख मुसलमान हैं तो फैसला यह किया जाता है कि ठाकुर को वोट दे दो, मुसलमान वोट दे ही देगा, इसलिए कि उसके पास इतना लायक आदमी नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस कंडीशन में हमारी औरतें कहां से इलेक्शन में आएंगी।

प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, मैं इनके सामने एक वाकया बयान करना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि हम किस माहौल में हैं और हमने क्या समाज बनाया है। मेरी मां की सगी बड़ी बहन ने सन् 36 में लखनऊ से कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा बुर्का पहनकर। हमारी समाज 80 साल के बाद क्या इस बात के लिए तैयार है कि मैं अपनी बेटी को बुर्का पहनकर इलेक्शन में ले जाऊँ? क्या कहलाएगी वह, आतंकवादी, बैकवर्ड और दकियानूसी? यह हमने समाज बनाया है। हम ऐसी शक्ल में खड़े हैं। इस पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी 50 और 55 की थी, आज हम 27 पर आ गए। हमको यह खौफ है, हम जानते हैं, हम इस सरकार से मुहब्बत करते हैं, हमको कांग्रेस से मुहब्बत और अकीदत है, हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं लेकिन कांग्रेस से पूछते हैं कि हम वोट डालने की मशीन कब तक रहेंगे, कब तक हमारे साथ यह होगा? अगर गिल कमीशन की बात मान ली जाती तो इन पार्टियों में यह कहा जाता कि 33 परसेंट रिजर्वेशन किया जाए, लेकिन यह नहीं किया गया, इसलिए कि लड़कियां, औरतें कैंडिडेट नहीं बन सकती थीं, इलेक्शन नहीं जीत सकती थीं। पार्टियां कमजोर हो जातीं, पार्टियों को कमजोर करना मकसद नहीं है, पार्लियामेंट कमजोर हो जाए, कोई बात नहीं है। हम तरक्की कर रहे हैं! यह हमारा मनसब है। मैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ और अपने कांग्रेस के भाइयों से और लेफ्ट के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि यह बिल आप पास करें, हम आपके साथ रहेंगे लेकिन इस बात का वायदा कीजिए और अज्म कीजिए कि आप जब 33 परसेंट का रिजर्वेशन कर रहे हैं तो इसमें 15 से 17 परसेंट मुसलमानों का रिजर्वेशन यकीनी बनाइए और यह कहिए, अगर आपने यह नहीं किया तो यकीनन आप हम लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे।

इन अल्फाज के साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आपकी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। मैं जानता हूँ कि हिन्दुस्तान में आप ही एक अकेली पार्टी हैं, लेकिन हमें नज़रअंदाज मत कीजिए, हमारे दिल में जो शक-ओ-शुबहात हैं, उनको आप पार्टी के अंदर यह कानून लाकर पूरा कीजिए कि हम रिजर्वेशन जब देंगे तो मुसलमानों को, बैकवर्ड को और दलितों को 20 से 25 परसेंट इन 33 परसेंट में से देंगे। शुक्रिया।

† جناب محمد ادیب (اتر پردیش) : شکر یہ، پچھلے دو دنوں سے جو کچھ ہاؤس میں، میں نے دیکھا، اس سے بڑا دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے۔ اس کو بیان کرنے کا اظہار، میں اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں :

رنگ و گل کا ہے نہ سلیقہ، نہ بہاروں کا شعور

ہائے کن ہاتھوں کی تقدیر میں تاریک حنا ٹھہری

حالت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا، بہت افسوسناک ہے، لیکن اس بات کی بھی ایک خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے مختلف لیڈران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دیہات اور کھلیہاتوں سے عورتوں کو لائیں گے اور ہندوستان کے اس سب سے بڑے مندر میں، جہاں قانون بنائے جاتے ہیں، وہاں لاکر ایمپاورمینٹ دیں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں کی عورتیں آج روز جہیز کی شکار ہو رہی ہیں، ادھر ہماری توجہ نہیں ہے، وہاں کی عورتوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، تعلیم نہیں مل رہی ہے، لیکن ہم پارلیمنٹ میں ان کو لانے کے لئے بہت اتسک ہیں۔ جب سب کی یہ رائے ہے تو میری بھی یہی رائے ہے۔ میرے دل کی جو کیفیت ہے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے تیواری جی نے بیان کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے لئے ایک تشویش کا لمحہ آ گیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، میں نے دیکھا ہے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے الیکشنوں میں، طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تین لاکھ ٹھاکر ہیں اور چار لاکھ مسلمان ہیں تو فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھاکر کو ووٹ دے دو، مسلمان تو ووٹ دے ہی دے گا، اس لئے کہ اس کے پاس اتنا لائق آدمی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کنٹیشن میں ہماری عورتیں کہاں سے الیکشن میں آئیں گی۔

پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں، میں ان کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس ماحول میں ہیں اور ہم نے کیا سماج بنایا ہے۔ میری ماں کی سگی بڑی بہن نے سن 1936ء میں لکھنؤ سے کانگریس کی طرف سے مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑا تھا برقعہ پہن کر۔ ہمارا سماج 80 سال کے بعد کیا اس بات کے لئے تیار ہے کہ میں اپنی بیٹی کو

† [Transliteration in Urdu Script]

برقعہ پہن کر الیکشن میں لے جاؤں؟ کیا کہلانے گی وہ؟ آتک-وادى، بیک-ورڈ اور دقياunosى۔ یہ ہم نے سماج بنایا ہے۔ ہم ایسی شکل میں گھڑے ہیں۔ اس پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی 50 اور 55 کی تھی، آج ہم 27 پر آگئے۔ ہم کو یہ خوف ہے، ہم جانتے ہیں، ہم اس سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہم کو کانگریس سے محبت اور عقیدت ہے، ہم کانگریس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن کانگریس سے پوچھتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالنے کی مشین کب تک رہیں گے، کب تک ہمارے ساتھ یہ ہوگا؟ اگر گل کیمشن کی بات مان لی جاتی تو ان پارٹیوں میں یہ کہا جاتا کہ 33 فیصد رزرویشن کیا جانے، لیکن یہ نہیں کیا گیا، اسلئے کہ لڑکیاں، عورتیں کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتی تھیں، الیکشن نہیں جیت سکتی تھیں۔ پارٹیاں کمزور ہو جاتیں، پارٹیوں کو کمزور کرنا مقصد نہیں ہے، پارلیمنٹ کمزور ہو جانے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا منصب ہے۔ میں آج پرانم منسٹر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اپنے کانگریس کے بھائیوں سے اور لیفٹ کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بل آپ پاس کریں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن اس بات کا وعدہ کیجئے اور عزم کیجئے کہ آپ جب 33 فیصد کا رزرویشن کر رہے ہیں تو اس میں 15 سے 17 فیصد مسلمانوں کا رزرویشن یقینی بنائیے اور یہ کہئے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یقیناً آپ ہم لوگوں کے ساتھ نا انصافی کریں گے۔

ان الفاظ کے ساتھ میں پرانم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، آپ کی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں کیوں کہ میرے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں آپ کی ایک اکیلی پارٹی ہے، لیکن ہمیں نظر انداز مت کیجئے، ہمارے دل میں جو شک و شبہات ہیں، ان کو آپ پارٹی کے اندر یہ قانون لاکر پورا کیجئے کہ ہم رزرویشن جب دیں گے، تو مسلمانوں کو، بیک-ورڈ کو اور دلتوں کو 20 سے 25 فیصد ان 33 فیصد میں سے دیں گے۔

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष जी, पहले तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और समर्थन के साथ अपनी बात भी यहां कहना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, यह सबको मालूम है, लेकिन सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण बिल को United Front की सरकार के समय में लाया गया था, यह बात भी आपको कहनी चाहिए। हमें संविधान संशोधन बिल के लिए दो-तिहाई मत चाहिए, लेकिन दो-तिहाई का मतलब यह नहीं है कि केवल हमने किया है, आप यह राजनीति मत कीजिए, मैं कांग्रेसियों से यह बात कह रहा हूँ। इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि इसके लिए बहुत बार प्रयास किया गया था, लेकिन किसी न किसी कारण से यह नहीं हो पाया। कल यह ऐतिहासिक बिल, एक ऐतिहासिक अवसर पर, एक इतिहास की रचना के लिए हम इस संसद में लाए थे, लेकिन कल हम इसे पास नहीं कर पाए और इस बीच एक दूसरा इतिहास भी आपने रच दिया, ऐसा क्यों हुआ? जहां तक हमारे इस सदन की गरिमा और मर्यादा की बात है, कल इस सदन को क्यों चार बार adjourn करना पड़ा, क्यों आपने इसमें दखल नहीं दिया, क्यों आपने इस बिल को कल पारित करने की कोशिश नहीं की? यह सवाल आपके ऊपर आता है और आज भी जो घटना घटी है, यह हमारे सदन के लिए अच्छी नहीं है। मैं दोनों की निंदा करता हूँ। मैं यह कहता हूँ कि अगर सदन की गरिमा को बनाए रखना है, तो Treasury Benches को किसी भी बिल को सदन में रखने से पहले, सदन को confidence में लेना चाहिए।

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

सभापति जी, कहा जा रहा है कि आज़ादी के 63 सालों के बाद आज यह बिल पास हो रहा है। कांग्रेस की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन इन 63 सालों में आपने कितने सालों तक राज किया और 1991 से 1995 के बीच आप यह बिल क्यों नहीं ला पाए, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। Do not play politics with women. You respect them. आप उनको सम्मान दीजिए और मर्यादा के साथ इस बिल को पारित कीजिए। खाली बिल में रिजर्वेशन की बात नहीं है, लोक सभा में या विधान सभाओं में आने की बात नहीं है, इसके साथ पूरे देश में नारी जाति को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, तभी उनके empowerment की बात आती है...**(व्यवधान)**... जब women empowerment की बात आती है, तो हर जगह, घर से लेकर संसद तक, हर जगह उनके पूरे सम्मान की बात होनी चाहिए। रोजाना अखबारों में जो हम पढ़ते हैं, क्या इसमें हमारी women empowerment की कोई बात आती है? मैं गुज़ारिश करूंगा कि पूरा सदन इस बिल का समर्थन करते हुए यह भी कहे कि महिलाओं का भारत में इस तरह से सम्मान होना चाहिए ताकि हमसे दुनिया सीखे कि महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI ABDUL WAHAB PEEVEE (Kerala): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak. I rise here, on behalf of the Indian Union Muslim League to speak on the Bill. We are discussing on implementation of the reservation for women. But, we hope, the UPA Government, under the leadership of Dr. Manmohan Singh and the UPA Chairperson, would give adequate representation to minorities, especially the Muslims and the backward communities. I wonder, in future, we may have to have another Bill reserving 33 per cent seats for males if this trend continues in the House. After ten years, I think, another Bill has to be brought in this same House even if I am not there because I am retiring on April 2. I am lucky to be here when reservation of seats is being considered in the House. But if this trend continues, the male Members will be in minority here. ...**(Interruptions)**... Brinda Karatji was telling about the representation in Hyderabad Corporation and all that. I thank her for making a mention of Hyderabad Municipality. But what is happening in West Bengal? ...**(Interruptions)**... Muslims

are 25 per cent of the population in West Bengal. What is the representation of Muslims in West Bengal? ...*(Interruptions)*... You are ruling that State. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Mr. Abdul Wahab, you have limited time. ...*(Interruptions)*... Please complete your speech. ...*(Interruptions)*... Mrs. Karat, please allow the debate to go on. ...*(Interruptions)*... I request you to please resume your place. ...*(Interruptions)*... Mr. Abdul Wahab, you have three minutes and two minutes have already gone. So, you have one minute left.

SHRI ABDUL WAHAB PEEVEE: I just mentioned two or three places, namely, West Bengal and Kerala. Kerala has adequate number because our party is there. Unfortunately, in West Bengal our party is not there. Anyway, we hope that in future adequate representation, 25 per cent, will come from West Bengal and other States. Sir, I once again thank you for having given me this opportunity, and I support the Bill.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much.

श्री परिमल नथवानी (झारखंड): सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी का और सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इस ऐतिहासिक बिल का शुरु से समर्थन किया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सारी राजनीतिक पार्टियों ने जो कुछ लोगों को छोड़कर समर्थन किया है, उसके लिए मैं अपनी खुशी व्यक्त करता हूँ। सर, मैं इसलिए अपनी खुशी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं झारखंड को represent करता हूँ। झारखंड से लोक सभा के अंदर एक भी महिला चुन कर नहीं आई है। झारखंड में assembly के अंदर भी महिलाओं की संख्या double digit में नहीं पहुंची है, जिसको हम दस कह सकते हैं। इस बिल के माध्यम से हमारे झारखंड की बहनों और महिलाओं को खूब लाभ पहुंचेगा। इतना ही नहीं, यहां से पंचायती राज की बात की जा रही थी। जब से झारखंड अलग राज्य बना है, तब से वहां पंचायतों का चुनाव भी नहीं हुआ है। झारखंड में पंचायतों के चुनाव होंगे, तो जैसे यहां श्रीमती वृंदा कारत जी ने कहा कि पंचायती राज से महिलाओं का योगदान शुरु होता है, तो मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार और भारत सरकार को मिलकर झारखंड के अंदर भी पंचायती राज को लाने का प्रयास करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ कोई मामला है। मैं फिर से पूरे सदन को धन्यवाद देता हूँ और मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ।

सुश्री अनुसुइया उइके (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस विधेयक में महिला सशक्तिकरण, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से बराबरी का दर्जा देने के लिए जो महिला आरक्षण बिल यहां प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ और इसकी प्रशंसा करती हूँ। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने सन् 1996 में पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लगातार इस महिला आरक्षण को लागू करने का प्रयास किया और उसका ही परिणाम यह है कि आज महिला आरक्षण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हो पाया। मैं इसके लिए हमारी पार्टी के नेता, माननीय जेटली जी, समस्त वरिष्ठ नेताओं और विरोधी दल के तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष की प्रमुख पार्टी है, उसने महिला आरक्षण बिल को दिल से समर्थन दिया है और मैं यह बात दावे से कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होती, तो वह महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं करती...*(व्यवधान)*... माननीय सभापति महोदय...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: प्लीज़....प्लीज़.... बैठ जाइए।...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): आपकी पार्टी ने किया था।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज़ बैठ जाइए।...(व्यवधान)...

सुश्री अनुसुइया उइके: माननीय सभापति महोदय, देश की आधी जनसंख्या ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज़, बैठ जाइए.... प्लीज़ बैठ जाइए.. समय कम है, प्लीज़।

सुश्री अनुसुइया उइके: माननीय सभापति महोदय, देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, फिर भी उन्हें समान और पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही थी और आज़ादी के 62 वर्ष उपरांत आज यह मांग पूरी होने जा रही है, इसलिए यह महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। इसके लिए मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के नेता और अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: No interventions please.

सुश्री अनुसुइया उइके: माननीय सभापति महोदय, मझे एक बात और कहनी है कि यहां पर हमारे जितने भी सांसद भाई हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकार देने की बात कही है। आज मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगी और यह मांग रखती हूँ कि जिस तरह से पांच साल के लिए प्रधान मंत्री पुरुष होते हैं, उसी प्रकार महिला को भी पांच साल के लिए प्रधान मंत्री होना चाहिए।...(व्यवधान).... मंत्रिमंडल में भी 33 परसेंट महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए।...(व्यवधान)...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (Bihar): Sir, this is the best speech. ...(Interruptions)...

श्री सभापति: प्लीज़... आपका समय खत्म हो रहा है।...(व्यवधान)...

सुश्री अनुसुइया उइके: माननीय सभापति महोदय ...

श्री सभापति: अब आप खत्म कीजिए।...(व्यवधान).... प्लीज़...(व्यवधान).... आपके तीन मिनट पूरे हो चुके हैं।

सुश्री अनुसुइया उइके: माननीय सभापति महोदय, मैं सभी पुरुष भाइयों से कहना चाहूंगी कि आपका कोई अधिकार कम करके हम उसमें से कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमने तो सदैव ही आपको जो भी अधिकार मिलते रहे हैं, उन्हें प्रदान करने में कभी भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई, किंतु आज जब महिलाओं को कुछ अधिकार देने की बात हो रही है, तो उसमें एकजुटता दिखाई दे रही है, इसके लिए मैं सदन के समस्त सांसद भाइयों का अपनी ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद।

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman Sir, I should begin by expressing my deep sorry over some abnormal developments that took place in this House in the last two days. Mr. Chairman, on behalf of our Government I owe you profound apology on the disrespect that was shown to you and the office bearers. These things should never have happened. They have happened and we have to reflect as to how we can streamline our functioning in future that these things don't take place. Mr. Chairman, despite these abnormal developments the unanimity or near unanimity that has been displayed while considering this landmark legislation is a living proof that the health of Indian democracy is sound and is in the right place. I, therefore, congratulate the hon. Leader of the Opposition, the leaders of all other political parties whose cooperation has made it possible for us to enact a truly historic legislation.

This is a momentous development in the long journey of empowering our women. Mr. Chairman, Sir, that process began with the freedom. When it dawned, our leaders have the wisdom to give all persons — men and women — of the age of 21 years the voting rights. Subsequently, Shri Rajivji, lowered the voting age to 18 years. But, we have also to recognize that despite various efforts that have been made in the Independent India for social and economic development, our women have faced enormous difficulties even when we talk in terms of the benefits of the processes of social and economic development. Our women faced is crimination at home. There is domestic violence. They face discrimination in their unequal access to education, in healthcare, etc. All these things have to end if India is to realize the full potential of its social and economic development. The Bill that is going to pass today is a historic step forward, is a giant step forward in strengthening the process of emancipation of India's womanhood. It is a celebration of our womanhood. It is a celebration of India's regard and respect in our ancient culture and civilization for our women. It is a great remembrance of all those brave women who fought for India's Independence. On this occasion, my thoughts go to Kasturba Mata, Dr. Annie Besant, Smt. Kamla Nehru, Smt. Sarojni Naidu, Rajkumari Amrit Kaur, Smt. Vijayalakshmi Pandit, Smt. Indira Gandhi. All these brave daughters of India have fought and contributed enormously to the success of our freedom struggle. What we are going to enact today is a small token of our homage to the sacrifices that our women have made in the processes of nation building, freedom struggle and all other nation building activities. I recall also the contribution of late Smt. Gita Mukherjee. She was the Chairperson of the Standing Committee which reported on the first Bill that came before Parliament. I also thank Smt. Jayanti Natarajan, the Chairperson of the Standing Committee, which processed this important Bill.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, don't mention the name of Shri Natchiappan. He was the one who opposed the Bill.

DR. MANMOHAN SINGH: But, I should also mention his name...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Men have also contributed...*(Interruptions)*...

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, some hon. Members have expressed some reservations that they would have liked to see some recognition of disabilities of the Minorities, the disabilities of backward classes, of the SC/ST. I do recall and I do recognize that our Minorities have not got an adequate share of the fruits of our development. Our Government is committed to work sincerely for the empowerment of our minority communities. There are many other ways. The process has already begun. We will attend to this task with all sincerity. This Bill is not an anti-minority Bill; it is not an anti-Scheduled Castes Bill; it is not an anti-Scheduled Tribes Bill. It is a Bill that carries forward the process of emancipation of our women. It is a major and a joint step forward. It is a historically occasion that calls for celebration. I thank each one of the Members of this august House. I also thank, Mr. Chairman, your goodself and Mr. Deputy Chairman for your enormous contribution. At the end of the acrimonious events, it is the ending that matters. As

somebody has said, “आगाज को कोई पूछता नहीं, अंजाम अच्छा हो आदमी का।” So, with these words, once again, I express my joy that we are going to enact this very historic path-breaking legislation.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI: M. VEERAPPA MOILY): Mr. Chairman, Sir, after having heard the 27 speakers, commencing from Arun Jaitleyji and, finally, finale or climax which was spoken out by our beloved Prime Minister, I don't want to speak much. But, today is a historical day because all of us are paying our debt to our mother. This is the greatest day. The necessity of such a legislation is all the more, today, when the percentage of women in this world's largest democracy has not exceeded 11.25 per cent. In fact, the world average itself is 19 per cent, even the Asian average is 18.7 per cent. That's why, today, the time has come to act and act boldly and with a vision. The momentous days and acts will not come that easily at a normal time. As it is said, any step up for a reform as a precept is ultimately the precept of creative destruction. Whatever happened yesterday and today, I must, ultimately, commend the tolerance, resilience and also the great, great meticulous willpower demonstrated by our great Chairman to withstand that turbulence that was unprecedented. And, yes, he is, now, witnessing today this kind of convergence of unity in diversity. I must also say that our civilization, our history, our philosophy, our religion continue to inspire the people. Our commitment to the principle of non-violence was heralded by the entire world. Today, we have an opportunity to demonstrate to the world that when it comes to the progressive measures our country will not fall back or look back, and that is the great step that was taken today.

I must congratulate all the hon. Members, irrespective of Parties, who have rendered whole-hearted support, which is not a mechanical support. There are some misgivings which have been expressed both inside the House and also outside the House. I need to clarify a few. After passing of this Constitutional amendment, there will be a law which will be passed by the Parliament, which will look into the determination of seats and also decision on quotas, so that some of the concerns expressed today, can, definitely, be addressed. Determination of seats and also reservation will be addressed by a separate law, just like the Delimitation Act. So, that will be addressed. We need to look into those matters and we will come out with a legislation. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, you said, “it is ‘quota’.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: That was wrongly said..*(Interruptions)*.. That was slip of tongue. That was wrongly said. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): That should be clarified. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I think it is clarified.

The last point which I would like to clarify is about the reservation of the OBCs, minorities and the rest. As you all know, as on today, we have reservation only for the Scheduled Castes/

Scheduled Tribes. We do not have the data for the entire nation because after 1931, no national Census has been done. A backward class in one State may not be the backward class in another State. If we want real reservation for OBCs and minorities, we need to address many other issues. I do not want to prolong this. I commend this Bill for consideration and passing by this House. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. This concludes the discussion on the Bill.

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: सर, हमारा दो मिनट का समय बचा है, उसमें से मैं एक मिनट का समय लूंगा।

श्री सभापति: जी, फरमाइए।

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: सभापति महोदय, अभी लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन वह समझते हैं कि होना चाहिए, लेकिन डाटा नहीं है इसलिए नहीं हुआ। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। हम लोगों ने अपनी बात कही कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए, अब आप इस पर ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, उसके लिए आप मझे परमिट कर दीजिए।
...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: You wanted to say something else.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Yes, Sir, I want to say something else. मझे यह उम्मीद थी कि हमने जो अपनी बात रखी थी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुमारी बहन मायावती जी ने रखी थी, उन्होंने जो पत्र में लिखकर कहा था उसको कंसीडर करते हुए शायद यह बिल आज वोटिंग के लिए नहीं रखा जाएगा, उसमें अमेंडमेंट्स करने के बाद आएगा, लेकिन ऐसा मझको नहीं लगता है। जैसा कि आप ने कहा आप वोटिंग के लिए बिल को रखने जा रहे हैं और चूंकि इसमें गरीब महिलाओं को चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट हो, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हो, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, बैकवर्ड हो या अपर कास्ट की हो, उनकी अनदेखी की जा रही है। इसलिए इस वोटिंग में बहुजन समाज पार्टी participate नहीं करेगी। क्योंकि हम बिल के इस स्वरूप से असहमत हैं और इस बिल पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए, हमारी पार्टी के लोग इस वोटिंग से अपना walk out करते हैं।

(At this stage, some Hon. Members left the Chamber.)

SHRI SITARAM YECHURY: Sir...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Now, what is it?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I have a matter that I think merits your consideration and consideration of the House that after this process is over, I think the House must place on record our deep sense of appreciation to our staff and the marshals for the work they have done and permitted this very, very meaningful discussion. That must be placed on record.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्रीमती माया सिंह: सभापति जी, हम आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से यह आश्वासन चाहते हैं कि यह महिला आरक्षण बिल आज यहां से पास हो रहा है, यह बिल राज्य सभा से पास हो जाएगा। अभी आधा काम हुआ है, लोक सभा में इसी सत्र में ...(व्यवधान).... बल्कि इसी सत्र में लोक सभा से पास होना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion for consideration of the Bill to vote. ...*(Interruptions)*... Please, hon. Members do not interrupt now. ...*(Interruptions)*... The question is,

That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.

The House divided

MR. CHAIRMAN: Ayes - 186
 Noes - 01

AYES — 186

Abdul Wahab Peevee, Shri
Achuthan, Shri M.P.
Adeeb, Shri Mohammed
Adik, Shri Govindrao Wamanrao
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S.S.
Alvi, Shri Raashid
Amin, Shri Mohammed
Anand Sharma, Shri
Anbalagan, Shri S.
Ansari, Shri Ali Anwar
Antony, Shri A.K.
Apte, Shri Balavant *alias* Bal
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Bagrodia, Shri Santosh
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajaj, Shri Rahul
Bajwa, Shri Varinder Singh
Balaganga, Shri N.
Batra, Shri Shadi Lal
Bhartia, Shrimati Shobhana
Budania, Shri Narendra
Chakraborty, Shri Shyamal
Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chatterjee, Shri Prasanta
Chaturvedi, Shri Lalit Kishore
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chavan, Shri Prithviraj
Condpan, Shri Silvius
Daimary, Shri Biswajit
Darda, Shri Vijay Jawaharlal
Das, Shri Kumar Deepak
Dave, Shri Anil Madhav
Deora, Shri Murli
Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao
Dhawan, Shri R.K.
Dhinakaran, Shri T.T.V.
Dhoot, Shri Rajkumar
Dwivedi, Shri Janardan
Elavarasan, Shri A.
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gnanadesikan, Shri B.S.
Govindarajar, Shri N.R.
Gujral, Shri Naresh
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Heptulla, Dr. (Shrimati) Najma A.
Ismail, Shri K.E.
Jaitley, Shri Arun
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Jinnah, Shri A.A.
Jois, Shri M. Rama
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanimozhi, Shrimati
Kannan, Shri P.

Karan Singh, Dr.
Karat, Shrimati Brinda
Katiyar, Shri Vinay
Keishing, Shri Rishang
Kesari, Shri Narayan Singh
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Khuntia, Shri Rama Chandra
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kore, Dr. Prabhakar
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Krishna, Shri S.M.
Kshatriya, Prof. Alka Balram
Kurien, Prof. P.J.
Lad, Shri Anil H.
Lalhming Liana, Shri
Madhu, Shri Penumalli
Mahendra Prasad, Dr.
Maitreya, Dr. V.
Majhi, Shri Bhagirathi
Majitha, Shri Raj Mohinder Singh
Malaisamy, Dr. K.
Malihabadi, Shri Ahmad Saeed
Mangala Kisan, Shri
Mathur, Shri Om Prakash
Mishra, Shri Kalraj
Mohanty, Shri Kishore Kumar
Mohapatra, Shri Pyarimohan
Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh
Moinul Hussan, Shri
Mukut Mithi, Shri
Naidu, Shri M. Venkaiah
Naik, Shri Pravinonandra Rughnathji

Naik, Shri Shantaram Laxman
Nandamuri Harikrishna, Shri
Nandi Yellaiah, Shri
Natarajan, Shrimati Jayanthi
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Nathwani, Shri Parimal
Nayak, Dr. Radhakant
Pany, Shri Rudra Narayan
Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh
Pasha, Shri Syed Azeez
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Kanjibhai
Patel, Shri Surendra Motilal
Pathak, Shri Saman
Pilania, Dr. Gyan Prakash
Pradhan, Shrimati Renubala
Prasad, Shri Ravi Shankar
Punj, Shri Balbir
Rai, Shrimati Kusum
Raja, Shri D.
Rajan, Shri P.R.
Rajeeve, Shri P.
Ram Prakash, Dr.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K. Keshava
Rao, Shri K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rashtrapal, Shri Praveen
Ratanpuri, Shri G.N.
Ratna Bai, Shrimati T.
Raut, Shri Bharkumar
Raut, Shri Sanjay

Ravi, Shri Vayalar
Rebello, Ms. Mabel
Reddy, Shri G. Sanjeeva
Reddy, Shri M.V. Mysura
Reddy, Dr. N. Janardhana
Reddy, Dr. T. Subbarami
Roy, Shri Abani
Roy, Shri Tarini Kanta
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Rupala, Shri Parshottam Khodabhai
Rupani, Shri Vijaykumar
Sabharwal, Shri Dharam Pal
Sahani, Prof. Anil Kumar
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Sai, Shri Nand Kumar
Sanghi, Shri Gireesh Kumar
Sangma, Shri Thomas
Sarkar, Shri Matilal
Seelam, Shri Jesudasu
Sen, Shri Tapan Kumar
Sengupta, Shri Arjun Kumar
Shafi, Shri Mohammad
Shanappa, Shri K.B.
Shanta Kumar, Shri
Sharma, Shri Raghunandan
Sharma, Shri Satish Kumar
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Shri Arjun
Singh, Shri Ishwar
Singh, Shri Jai Prakash Narayan
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shrimati Maya
Singh, Shri N.K.

Singh, Shri R.C.
Singh, Shri Shivpratap
Singh, Sardar Tarlochan
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Solanki, Shri Kaptan Singh
Soni, Shrimati Ambika
Soz, Prof. Saif-ud-Din
Stanley, Shrimati Vasanthi
Swaminathan, Prof. M.S.
Taimur, Shrimati Syeda Anwara
Tariq Anwar, Shri
Thakor, Shri Natuji Halaji
Thakur, Dr. C.P.
Thakur, Dr. Prabha
Thakur, Shrimati Viplove
Tiriya, Ms. Sushila
Tiwari, Shri Sivanand
Trivedi, Shri Y.P.
Uikey, Miss Anusuiya
Vasan, Shri G.K.
Vatsyayan, Dr. (Shrimati) Kapila
Verma, Shri Vikram
Vijayaraghavan, Shri A.
Vora, Shri Motilal
Vyas, Shri Shreegopal
Waghmare, Dr. Janardhan
Yechury, Shri Sitaram
Zhimomi, Shri Khekiho

NOES — 1

Shri Sharad Anantrao Joshi

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill. We will take up clauses 2 to 6.

The House divided.

MR. CHAIRMAN: Ayes - 186

Noes - 1

AYES — 186

Abdul Wahab Peevee, Shri
Achuthan, Shri M.P.
Adeeb, Shri Mohammed
Adik, Shri Govindrao Wamanrao
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S.S.
Alvi, Shri Raashid
Amin, Shri Mohammed
Anand Sharma, Shri
Anbalagan, Shri S.
Ansari, Shri Ali Anwar
Antony, Shri A.K.
Apte, Shri Balavant *alias* Bal
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Bagrodia, Shri Santosh
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajaj, Shri Rahul
Bajwa, Shri Varinder Singh
Balaganga, Shri N.
Batra, Shri Shadi Lal
Bhartia, Shrimati Shobhana
Budania, Shri Narendra
Chakraborty, Shri Shyamal
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chatterjee, Shri Prasanta
Chaturvedi, Shri Lalit Kishore

Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chavan, Shri Prithviraj
Condpan, Shri Silvius
Daimary, Shri Biswajit
Darda, Shri Vijay Jawaharlal
Das, Shri Kumar Deepak
Dave, Shri Anil Madhav
Deora, Shri Murli
Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao
Dhawan, Shri R.K.
Dhinakaran, Shri T.T.V.
Dhoot, Shri Rajkumar
Dwivedi, Shri Janardan
Elavarasan, Shri A.
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gnanadesikan, Shri B.S.
Govindarajar, Shri N.R.
Gujral, Shri Naresh
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Heptulla, Dr. (Shrimati) Najma A.
Ismail, Shri K.E.
Jaitley, Shri Arun
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Jinnah, Shri A.A.
Jois, Shri M. Rama
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanimozhi, Shrimati
Kannan, Shri P.
Karan Singh, Dr.
Karat, Shrimati Brinda

Katiyar, Shri Vinay
Keishing, Shri Rishang
Kesari, Shri Narayan Singh
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Khuntia, Shri Rama Chandra
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kore, Dr. Prabhakar
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Krishna, Shri S.M.
Kshatriya, Prof. Alka Balram
Kurien, Prof. P.J.
Lad, Shri Anil H.
Lalhming Liana, Shri
Madhu, Shri Penumalli
Mahendra Prasad, Dr.
Maitreya, Dr. V.
Majhi, Shri Bhagirathi
Majitha, Shri Raj Mohinder Singh
Malaisamy, Dr. K.
Malihabadi, Shri Ahmad Saeed
Mangala Kisan, Shri
Mathur, Shri Om Prakash
Mishra, Shri Kalraj
Mohanty, Shri Kishore Kumar
Mohapatra, Shri Pyarimohan
Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh
Moinul Hussan, Shri
Mukut Mithi, Shri
Naidu, Shri M. Venkaiah
Naik, Shri Pravinonandra Rughnathji
Naik, Shri Shantaram Laxman
Nandamuri Harikrishna, Shri

Nandi Yellaiah, Shri
Natarajan, Shrimati Jayanthi
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Nathwani, Shri Parimal
Nayak, Dr. Radhakant
Pany, Shri Rudra Narayan
Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh
Pasha, Shri Syed Azeez
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Kanjibhai
Patel, Shri Surendra Motilal
Pathak, Shri Saman
Pilania, Dr. Gyan Prakash
Pradhan, Shrimati Renubala
Prasad, Shri Ravi Shankar
Punj, Shri Balbir
Rai, Shrimati Kusum
Raja, Shri D.
Rajan, Shri P.R.
Rajeeve, Shri P.
Ram Prakash, Dr.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K. Keshava
Rao, Shri K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rashtrapal, Shri Praveen
Ratanpuri, Shri G.N.
Ratna Bai, Shrimati T.
Raut, Shri Bharkumar
Raut, Shri Sanjay
Ravi, Shri Vayalar
Rebello, Ms. Mabel

Reddy, Shri G. Sanjeeva
Reddy, Shri M.V. Mysura
Reddy, Dr. N. Janardhana
Reddy, Dr. T. Subbarami
Roy, Shri Abani
Roy, Shri Tarini Kanta
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Rupala, Shri Parshottam Khodabhai
Rupani, Shri Vijaykumar
Sabharwal, Shri Dharam Pal
Sahani, Prof. Anil Kumar
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Sai, Shri Nand Kumar
Sanghi, Shri Gireesh Kumar
Sangma, Shri Thomas
Sarkar, Shri Matilal
Seelam, Shri Jesudasu
Sen, Shri Tapan Kumar
Sengupta, Shri Arjun Kumar
Shafi, Shri Mohammad
Shanappa, Shri K.B.
Shanta Kumar, Shri
Sharma, Shri Raghunandan
Sharma, Shri Satish Kumar
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Shri Arjun
Singh, Shri Ishwar
Singh, Shri Jai Prakash Narayan
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shrimati Maya
Singh, Shri N.K.
Singh, Shri R.C.
Singh, Shri Shivpratap

Singh, Sardar Tarlochan
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Solanki, Shri Kaptan Singh
Soni, Shrimati Ambika
Soz, Prof. Saif-ud-Din
Stanley, Shrimati Vasanthi
Swaminathan, Prof. M.S.
Taimur, Shrimati Syeda Anwara
Tariq Anwar, Shri
Thakor, Shri Natuji Halaji
Thakur, Dr. C.P.
Thakur, Dr. Prabha
Thakur, Shrimati Viplove
Tiriya, Ms. Sushila
Tiwari, Shri Sivanand
Trivedi, Shri Y.P.
Uikey, Miss Anusuiya
Vasan, Shri G.K.
Vatsyayan, Dr. (Shrimati) Kapila
Verma, Shri Vikram
Vijayaraghavan, Shri A.
Vora, Shri Motilal
Vyas, Shri Shreegopal
Waghmare, Dr. Janardhan
Yechury, Shri Sitaram
Zhimomi, Shri Khekiho

NOES — 1

Shri Sharad Anantrao Joshi

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

CLAUSES 2 to 6 were added to the Bill

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause 7. There is one Amendment (No.3) by Shri M.Veerappa Moily.

*CLAUSE 7 — Insertion of new article 334A.
Reservation of seats for women to cease after fifteen years*

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I beg to move:

3. That at page 4, lines 3 and 4, for the words, bracket and figure “Constitution (One Hundred and Eighth Amendment) Act, 2008”, the words, bracket and figure “Constitution (Ninety-sixth Amendment) Act, 2010” be *substituted*.

The House divided

MR. CHAIRMAN: Ayes - 186
 Noes - 1

AYES — 186

Abdul Wahab Peevee, Shri
Achuthan, Shri M.P.
Adeeb, Shri Mohammed
Adik, Shri Govindrao Wamanrao
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S.S.
Alvi, Shri Raashid
Amin, Shri Mohammed
Anand Sharma, Shri
Anbalagan, Shri S.
Ansari, Shri Ali Anwar
Antony, Shri A.K.
Apte, Shri Balavant *alias* Bal
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Bagrodia, Shri Santosh
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajaj, Shri Rahul
Bajwa, Shri Varinder Singh
Balaganga, Shri N.
Batra, Shri Shadi Lal

Bhartia, Shrimati Shobhana
Budania, Shri Narendra
Chakraborty, Shri Shyamal
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chatterjee, Shri Prasanta
Chaturvedi, Shri Lalit Kishore
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chavan, Shri Prithviraj
Condpan, Shri Silvius
Daimary, Shri Biswajit
Darda, Shri Vijay Jawaharlal
Das, Shri Kumar Deepak
Dave, Shri Anil Madhav
Deora, Shri Murl
Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao
Dhawan, Shri R.K.
Dhinakaran, Shri T.T.V.
Dhoot, Shri Rajkumar
Dwivedi, Shri Janardan
Elavarasan, Shri A.
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gnanadesikan, Shri B.S.
Govindarajar, Shri N.R.
Gujral, Shri Naresh
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Heptulla, Dr. (Shrimati) Najma A.
Ismail, Shri K.E.
Jaitley, Shri Arun
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Jinnah, Shri A.A.

Jois, Shri M. Rama
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanimozhi, Shrimati
Kannan, Shri P.
Karan Singh, Dr.
Karat, Shrimati Brinda
Katiyar, Shri Vinay
Keishing, Shri Rishang
Kesari, Shri Narayan Singh
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Khuntia, Shri Rama Chandra
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kore, Dr. Prabhakar
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Krishna, Shri S.M.
Kshatriya, Prof. Alka Balram
Kurien, Prof. P.J.
Lad, Shri Anil H.
Lalhming Liana, Shri
Madhu, Shri Penumalli
Mahendra Prasad, Dr.
Maitreyan, Dr. V.
Majhi, Shri Bhagirathi
Majitha, Shri Raj Mohinder Singh
Malaisamy, Dr. K.
Malihabadi, Shri Ahmad Saeed
Mangala Kisan, Shri
Mathur, Shri Om Prakash
Mishra, Shri Kalraj
Mohanty, Shri Kishore Kumar
Mohapatra, Shri Pyarimohan
Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh

Moinul Hussan, Shri
Mukut Mithi, Shri
Naidu, Shri M. Venkaiah
Naik, Shri Pravinonandra Rughnathji
Naik, Shri Shantaram Laxman
Nandamuri Harikrishna, Shri
Nandi Yellaiah, Shri
Natarajan, Shrimati Jayanthi
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Nathwani, Shri Parimal
Nayak, Dr. Radhakant
Pany, Shri Rudra Narayan
Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh
Pasha, Shri Syed Azeez
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Kanjibhai
Patel, Shri Surendra Motilal
Pathak, Shri Saman
Pilania, Dr. Gyan Prakash
Pradhan, Shrimati Renubala
Prasad, Shri Ravi Shankar
Punj, Shri Balbir
Rai, Shrimati Kusum
Raja, Shri D.
Rajan, Shri P.R.
Rajeeve, Shri P.
Ram Prakash, Dr.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K. Keshava
Rao, Shri K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rashtrapal, Shri Praveen

Ratanpuri, Shri G.N.
Ratna Bai, Shrimati T.
Raut, Shri Bharatkumar
Raut, Shri Sanjay
Ravi, Shri Vayalar
Rebello, Ms. Mabel
Reddy, Shri G. Sanjeeva
Reddy, Shri M.V. Mysura
Reddy, Dr. N. Janardhana
Reddy, Dr. T. Subbarami
Roy, Shri Abani
Roy, Shri Tarini Kanta
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Rupala, Shri Parshottam Khodabhai
Rupani, Shri Vijaykumar
Sabharwal, Shri Dharam Pal
Sahani, Prof. Anil Kumar
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Sai, Shri Nand Kumar
Sanghi, Shri Gireesh Kumar
Sangma, Shri Thomas
Sarkar, Shri Matilal
Seelam, Shri Jesudasu
Sen, Shri Tapan Kumar
Sengupta, Shri Arjun Kumar
Shafi, Shri Mohammad
Shanappa, Shri K.B.
Shanta Kumar, Shri
Sharma, Shri Raghunandan
Sharma, Shri Satish Kumar
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Shri Arjun
Singh, Shri Ishwar

Singh, Shri Jai Prakash Narayan
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shrimati Maya
Singh, Shri N.K.
Singh, Shri R.C.
Singh, Shri Shivpratap
Singh, Sardar Tarlochan
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Solanki, Shri Kaptan Singh
Soni, Shrimati Ambika
Soz, Prof. Saif-ud-Din
Stanley, Shrimati Vasanthi
Swaminathan, Prof. M.S.
Taimur, Shrimati Syeda Anwara
Tariq Anwar, Shri
Thakor, Shri Natuji Halaji
Thakur, Dr. C.P.
Thakur, Dr. Prabha
Thakur, Shrimati Viplove
Tiriya, Ms. Sushila
Tiwari, Shri Sivanand
Trivedi, Shri Y.P.
Uikey, Miss Anusuiya
Vasan, Shri G.K.
Vatsyayan, Dr. (Shrimati) Kapila
Verma, Shri Vikram
Vijayaraghavan, Shri A.
Vora, Shri Motilal
Vyas, Shri Shreegopal
Waghmare, Dr. Janardhan
Yechury, Shri Sitaram
Zhimomi, Shri Khekiho

NOES — 1

Shri Sharad Anantrao Joshi

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

CLAUSE 7, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 8. There is one amendment (No. 4) by the hon. Minister.

CLAUSE 8 — Amendment not to affect representation in the House of the People or Legislative Assembly of a State or Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I move:

4. “That at page 4, lines 11 and 12, for the words, bracket and figure “Constitution (One Hundred and Eighth Amendment) Act, 2008”, the words, bracket and figure “Constitution (Ninety-sixth Amendment) Act, 2010” be *substituted*.

The House divided

MR. CHAIRMAN: Ayes - 186
 Noes - Nil

AYES — 186

Abdul Wahab Peevee, Shri
Achuthan, Shri M.P.
Adeeb, Shri Mohammed
Adik, Shri Govindrao Wamanrao
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S.S.
Alvi, Shri Raashid
Amin, Shri Mohammed
Anand Sharma, Shri
Anbalagan, Shri S.
Ansari, Shri Ali Anwar
Antony, Shri A.K.
Apte, Shri Balavant *alias* Bal
Ashwani Kumar, Shri

Azad, Shri Ghulam Nabi
Bagrodia, Shri Santosh
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajaj, Shri Rahul
Bajwa, Shri Varinder Singh
Balaganga, Shri N.
Batra, Shri Shadi Lal
Bhartia, Shrimati Shobhana
Budania, Shri Narendra
Chakraborty, Shri Shyamal
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chatterjee, Shri Prasanta
Chaturvedi, Shri Lalit Kishore
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chavan, Shri Prithviraj
Condpan, Shri Silvius
Daimary, Shri Biswajit
Darda, Shri Vijay Jawaharlal
Das, Shri Kumar Deepak
Dave, Shri Anil Madhav
Deora, Shri Murli
Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao
Dhawan, Shri R.K.
Dhinakaran, Shri T.T.V.
Dhoot, Shri Rajkumar
Dwivedi, Shri Janardan
Elavarasan, Shri A.
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gnanadesikan, Shri B.S.
Govindarajar, Shri N.R.
Gujral, Shri Naresh
Hariprasad, Shri B.K.

Hashmi, Shri Parvez
Heptulla, Dr. (Shrimati) Najma A.
Ismail, Shri K.E.
Jaitley, Shri Arun
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Jinnah, Shri A.A.
Jois, Shri M. Rama
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanimozhi, Shrimati
Kannan, Shri P.
Karan Singh, Dr.
Karat, Shrimati Brinda
Katiyar, Shri Vinay
Keishing, Shri Rishang
Kesari, Shri Narayan Singh
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Khuntia, Shri Rama Chandra
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kore, Dr. Prabhakar
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Krishna, Shri S.M.
Kshatriya, Prof. Alka Balram
Kurien, Prof. P.J.
Lad, Shri Anil H.
Lalhming Liana, Shri
Madhu, Shri Penumalli
Mahendra Prasad, Dr.
Maitreya, Dr. V.
Majhi, Shri Bhagirathi
Majitha, Shri Raj Mohinder Singh
Malaisamy, Dr. K.

Malihabadi, Shri Ahmad Saeed
Mangala Kisan, Shri
Mathur, Shri Om Prakash
Mishra, Shri Kalraj
Mohanty, Shri Kishore Kumar
Mohapatra, Shri Pyarimohan
Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh
Moinul Hussan, Shri
Mukut Mithi, Shri
Naidu, Shri M. Venkaiah
Naik, Shri Pravinonandra Rughnathji
Naik, Shri Shantaram Laxman
Nandamuri Harikrishna, Shri
Nandi Yellaiah, Shri
Natarajan, Shrimati Jayanthi
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Nathwani, Shri Parimal
Nayak, Dr. Radhakant
Pany, Shri Rudra Narayan
Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh
Pasha, Shri Syed Azeez
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Kanjibhai
Patel, Shri Surendra Motilal
Pathak, Shri Saman
Pilania, Dr. Gyan Prakash
Pradhan, Shrimati Renubala
Prasad, Shri Ravi Shankar
Punj, Shri Balbir
Rai, Shrimati Kusum
Raja, Shri D.
Rajan, Shri P.R.
Rajeeve, Shri P.

Ram Prakash, Dr.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K. Keshava
Rao, Shri K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rashtrapal, Shri Praveen
Ratanpuri, Shri G.N.
Ratna Bai, Shrimati T.
Raut, Shri Bharatkumar
Raut, Shri Sanjay
Ravi, Shri Vayalar
Rebello, Ms. Mabel
Reddy, Shri G. Sanjeeva
Reddy, Shri M.V. Mysura
Reddy, Dr. N. Janardhana
Reddy, Dr. T. Subbarami
Roy, Shri Abani
Roy, Shri Tarini Kanta
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Rupala, Shri Parshottam Khodabhai
Rupani, Shri Vijaykumar
Sabharwal, Shri Dharam Pal
Sahani, Prof. Anil Kumar
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Sai, Shri Nand Kumar
Sanghi, Shri Gireesh Kumar
Sangma, Shri Thomas
Sarkar, Shri Matilal
Seelam, Shri Jesudasu
Sen, Shri Tapan Kumar
Sengupta, Shri Arjun Kumar
Shafi, Shri Mohammad

Shanappa, Shri K.B.
Shanta Kumar, Shri
Sharma, Shri Raghunandan
Sharma, Shri Satish Kumar
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Shri Arjun
Singh, Shri Ishwar
Singh, Shri Jai Prakash Narayan
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shrimati Maya
Singh, Shri N.K.
Singh, Shri R.C.
Singh, Shri Shivpratap
Singh, Sardar Tarlochan
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Solanki, Shri Kaptan Singh
Soni, Shrimati Ambika
Soz, Prof. Saif-ud-Din
Stanley, Shrimati Vasanthi
Swaminathan, Prof. M.S.
Taimur, Shrimati Syeda Anwara
Tariq Anwar, Shri
Thakor, Shri Natuji Halaji
Thakur, Dr. C.P.
Thakur, Dr. Prabha
Thakur, Shrimati Viplove
Tiriya, Ms. Sushila
Tiwari, Shri Sivanand
Trivedi, Shri Y.P.
Uikey, Miss Anusuiya
Vasan, Shri G.K.
Vatsyayan, Dr. (Shrimati) Kapila

Verma, Shri Vikram
Vijayaraghavan, Shri A.
Vora, Shri Motilal
Vyas, Shri Shreegopal
Waghmare, Dr. Janardhan
Yechury, Shri Sitaram
Zhimomi, Shri Khekiho

NOES — NIL

The Motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

CLAUSE 8, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 1. There is one amendment (No. 2) by the hon. Minister.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I move:

2. That at page 1, lines 3 and 4, for the words, bracket and figure “Constitution (One Hundred and Eighth Amendment) Act, 2008”, the words, bracket and figure “Constitution (Ninety-sixth Amendment) Act, 2010” be *substituted*.

The House divided

MR. CHAIRMAN: Ayes - 186
 Noes - Nil

AYES — 186

Abdul Wahab Peevee, Shri
Achuthan, Shri M.P.
Adeeb, Shri Mohammed
Adik, Shri Govindrao Wamanrao
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S.S.
Alvi, Shri Raashid
Amin, Shri Mohammed
Anand Sharma, Shri
Anbalagan, Shri S.
Ansari, Shri Ali Anwar

Antony, Shri A.K.
Apte, Shri Balavant *alias* Bal
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Bagrodia, Shri Santosh
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajaj, Shri Rahul
Bajwa, Shri Varinder Singh
Balaganga, Shri N.
Batra, Shri Shadi Lal
Bhartia, Shrimati Shobhana
Budania, Shri Narendra
Chakraborty, Shri Shyamal
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chatterjee, Shri Prasanta
Chaturvedi, Shri Lalit Kishore
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chavan, Shri Prithviraj
Condpan, Shri Silvius
Daimary, Shri Biswajit
Darda, Shri Vijay Jawaharlal
Das, Shri Kumar Deepak
Dave, Shri Anil Madhav
Deora, Shri Murli
Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao
Dhawan, Shri R.K.
Dhinakaran, Shri T.T.V.
Dhoot, Shri Rajkumar
Dwivedi, Shri Janardan
Elavarasan, Shri A.
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gnanadesikan, Shri B.S.

Govindarajar, Shri N.R.
Gujral, Shri Naresh
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Heptulla, Dr. (Shrimati) Najma A.
Ismail, Shri K.E.
Jaitley, Shri Arun
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Jinnah, Shri A.A.
Jois, Shri M. Rama
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanimozhi, Shrimati
Kannan, Shri P.
Karan Singh, Dr.
Karat, Shrimati Brinda
Katiyar, Shri Vinay
Keishing, Shri Rishang
Kesari, Shri Narayan Singh
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Khuntia, Shri Rama Chandra
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kore, Dr. Prabhakar
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Krishna, Shri S.M.
Kshatriya, Prof. Alka Balram
Kurien, Prof. P.J.
Lad, Shri Anil H.
Lalhming Liana, Shri
Madhu, Shri Penumalli
Mahendra Prasad, Dr.
Maitreya, Dr. V.

Majhi, Shri Bhagirathi
Majitha, Shri Raj Mohinder Singh
Malaisamy, Dr. K.
Malihabadi, Shri Ahmad Saeed
Mangala Kisan, Shri
Mathur, Shri Om Prakash
Mishra, Shri Kalraj
Mohanty, Shri Kishore Kumar
Mohapatra, Shri Pyarimohan
Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh
Moinul Hussan, Shri
Mukut Mithi, Shri
Naidu, Shri M. Venkaiah
Naik, Shri Pravinonandra Rughnathji
Naik, Shri Shantaram Laxman
Nandamuri Harikrishna, Shri
Nandi Yellaiah, Shri
Natarajan, Shrimati Jayanthi
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Nathwani, Shri Parimal
Nayak, Dr. Radhakant
Pany, Shri Rudra Narayan
Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh
Pasha, Shri Syed Azeez
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Kanjibhai
Patel, Shri Surendra Motilal
Pathak, Shri Saman
Pilania, Dr. Gyan Prakash
Pradhan, Shrimati Renubala
Prasad, Shri Ravi Shankar
Punj, Shri Balbir
Rai, Shrimati Kusum

Raja, Shri D.
Rajan, Shri P.R.
Rajeeve, Shri P.
Ram Prakash, Dr.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K. Keshava
Rao, Shri K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rashtrapal, Shri Praveen
Ratanpuri, Shri G.N.
Ratna Bai, Shrimati T.
Raut, Shri Bharatkumar
Raut, Shri Sanjay
Ravi, Shri Vayalar
Rebello, Ms. Mabel
Reddy, Shri G. Sanjeeva
Reddy, Shri M.V. Mysura
Reddy, Dr. N. Janardhana
Reddy, Dr. T. Subbarami
Roy, Shri Abani
Roy, Shri Tarini Kanta
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Rupala, Shri Parshottam Khodabhai
Rupani, Shri Vijaykumar
Sabharwal, Shri Dharam Pal
Sahani, Prof. Anil Kumar
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Sai, Shri Nand Kumar
Sanghi, Shri Gireesh Kumar
Sangma, Shri Thomas
Sarkar, Shri Matilal
Seelam, Shri Jesudasu

Sen, Shri Tapan Kumar
Sengupta, Shri Arjun Kumar
Shafi, Shri Mohammad
Shanappa, Shri K.B.
Shanta Kumar, Shri
Sharma, Shri Raghunandan
Sharma, Shri Satish Kumar
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Shri Arjun
Singh, Shri Ishwar
Singh, Shri Jai Prakash Narayan
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shrimati Maya
Singh, Shri N.K.
Singh, Shri R.C.
Singh, Shri Shivpratap
Singh, Sardar Tarlochan
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Solanki, Shri Kaptan Singh
Soni, Shrimati Ambika
Soz, Prof. Saif-ud-Din
Stanley, Shrimati Vasanthi
Swaminathan, Prof. M.S.
Taimur, Shrimati Syeda Anwara
Tariq Anwar, Shri
Thakor, Shri Natuji Halaji
Thakur, Dr. C.P.
Thakur, Dr. Prabha
Thakur, Shrimati Viplove
Tiriya, Ms. Sushila
Tiwari, Shri Sivanand
Trivedi, Shri Y.P.

Uikey, Miss Anusuiya
 Vasan, Shri G.K.
 Vatsyayan, Dr. (Shrimati) Kapila
 Verma, Shri Vikram
 Vijayaraghavan, Shri A.
 Vora, Shri Motilal
 Vyas, Shri Shreegopal
 Waghmare, Dr. Janardhan
 Yechury, Shri Sitaram
 Zhimomi, Shri Khekiho

NOES — NIL

The Motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

CLAUSE 1, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In the Enacting Formula, there is one amendment (No. 1) by Shri M. Veerappa Moily.

ENACTING FORMULA

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I move:

1. That at page 1, line 1, for the word "Fifty-ninth" the word "Sixty-first" be *substituted*.

The House divided.

MR. CHAIRMAN: Ayes - 186
 Noes - Nil

AYES — 186

Abdul Wahab Peevee, Shri
 Achuthan, Shri M.P.
 Adeeb, Shri Mohammed
 Adik, Shri Govindrao Wamanrao
 Agarwal, Shri Ramdas
 Ahluwalia, Shri S.S.
 Alvi, Shri Raashid
 Amin, Shri Mohammed

Anand Sharma, Shri
Anbalagan, Shri S.
Ansari, Shri Ali Anwar
Antony, Shri A.K.
Apte, Shri Balavant *alias* Bal
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Bagrodia, Shri Santosh
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajaj, Shri Rahul
Bajwa, Shri Varinder Singh
Balaganga, Shri N.
Batra, Shri Shadi Lal
Bhartia, Shrimati Shobhana
Budania, Shri Narendra
Chakraborty, Shri Shyamal
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chatterjee, Shri Prasanta
Chaturvedi, Shri Lalit Kishore
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chavan, Shri Prithviraj
Condpan, Shri Silvius
Daimary, Shri Biswajit
Darda, Shri Vijay Jawaharlal
Das, Shri Kumar Deepak
Dave, Shri Anil Madhav
Deora, Shri Murli
Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao
Dhawan, Shri R.K.
Dhinakaran, Shri T.T.V.
Dhoot, Shri Rajkumar
Dwivedi, Shri Janardan
Elavarasan, Shri A.

Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gnanadesikan, Shri B.S.
Govindarajar, Shri N.R.
Gujral, Shri Naresh
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Heptulla, Dr. (Shrimati) Najma A.
Ismail, Shri K.E.
Jaitley, Shri Arun
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Jinnah, Shri A.A.
Jois, Shri M. Rama
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanimozhi, Shrimati
Kannan, Shri P.
Karan Singh, Dr.
Karat, Shrimati Brinda
Katiyar, Shri Vinay
Keishing, Shri Rishang
Kesari, Shri Narayan Singh
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Khuntia, Shri Rama Chandra
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kore, Dr. Prabhakar
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Krishna, Shri S.M.
Kshatriya, Prof. Alka Balram
Kurien, Prof. P.J.
Lad, Shri Anil H.
Lalhming Liana, Shri

Madhu, Shri Penumalli
Mahendra Prasad, Dr.
Maitreya, Dr. V.
Majhi, Shri Bhagirathi
Majitha, Shri Raj Mohinder Singh
Malaisamy, Dr. K.
Malihabadi, Shri Ahmad Saeed
Mangala Kisan, Shri
Mathur, Shri Om Prakash
Mishra, Shri Kalraj
Mohanty, Shri Kishore Kumar
Mohapatra, Shri Pyarimohan
Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh
Moinul Hussan, Shri
Mukut Mithi, Shri
Naidu, Shri M. Venkaiah
Naik, Shri Pravinonandra Rughnathji
Naik, Shri Shantaram Laxman
Nandamuri Harikrishna, Shri
Nandi Yellaiah, Shri
Natarajan, Shrimati Jayanthi
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Nathwani, Shri Parimal
Nayak, Dr. Radhakant
Pany, Shri Rudra Narayan
Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh
Pasha, Shri Syed Azeez
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Kanjibhai
Patel, Shri Surendra Motilal
Pathak, Shri Saman
Pilania, Dr. Gyan Prakash
Pradhan, Shrimati Renubala

Prasad, Shri Ravi Shankar
Punj, Shri Balbir
Rai, Shrimati Kusum
Raja, Shri D.
Rajan, Shri P.R.
Rajeeve, Shri P.
Ram Prakash, Dr.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K. Keshava
Rao, Shri K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rashtrapal, Shri Praveen
Ratanpuri, Shri G.N.
Ratna Bai, Shrimati T.
Raut, Shri Bharatkumar
Raut, Shri Sanjay
Ravi, Shri Vayalar
Rebello, Ms. Mabel
Reddy, Shri G. Sanjeeva
Reddy, Shri M.V. Mysura
Reddy, Dr. N. Janardhana
Reddy, Dr. T. Subbarami
Roy, Shri Abani
Roy, Shri Tarini Kanta
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Rupala, Shri Parshottam Khodabhai
Rupani, Shri Vijaykumar
Sabharwal, Shri Dharam Pal
Sahani, Prof. Anil Kumar
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Sai, Shri Nand Kumar
Sanghi, Shri Gireesh Kumar

Sangma, Shri Thomas
Sarkar, Shri Matilal
Seelam, Shri Jesudasu
Sen, Shri Tapan Kumar
Sengupta, Shri Arjun Kumar
Shafi, Shri Mohammad
Shanappa, Shri K.B.
Shanta Kumar, Shri
Sharma, Shri Raghunandan
Sharma, Shri Satish Kumar
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Shri Arjun
Singh, Shri Ishwar
Singh, Shri Jai Prakash Narayan
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shrimati Maya
Singh, Shri N.K.
Singh, Shri R.C.
Singh, Shri Shivpratap
Singh, Sardar Tarlochan
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Solanki, Shri Kaptan Singh
Soni, Shrimati Ambika
Soz, Prof. Saif-ud-Din
Stanley, Shrimati Vasanthi
Swaminathan, Prof. M.S.
Taimur, Shrimati Syeda Anwara
Tariq Anwar, Shri
Thakor, Shri Natuji Halaji
Thakur, Dr. C.P.
Thakur, Dr. Prabha
Thakur, Shrimati Viplove

Tiriya, Ms. Sushila
Tiwari, Shri Sivanand
Trivedi, Shri Y.P.
Uikey, Miss Anusuiya
Vasan, Shri G.K.
Vatsyayan, Dr. (Shrimati) Kapila
Verma, Shri Vikram
Vijayaraghavan, Shri A.
Vora, Shri Motilal
Vyas, Shri Shreegopal
Waghmare, Dr. Janardhan
Yechury, Shri Sitaram
Zhimomi, Shri Khekiho

NOES — NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up the Title.

The House divided

MR. CHAIRMAN: Ayes - 186
 Noes - Nil

AYES — 186

Abdul Wahab Peevee, Shri
Achuthan, Shri M.P.
Adeeb, Shri Mohammed
Adik, Shri Govindrao Wamanrao
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S.S.
Alvi, Shri Raashid
Amin, Shri Mohammed
Anand Sharma, Shri
Anbalagan, Shri S.

Ansari, Shri Ali Anwar
Antony, Shri A.K.
Apte, Shri Balavant *alias* Bal
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Bagrodia, Shri Santosh
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajaj, Shri Rahul
Bajwa, Shri Varinder Singh
Balaganga, Shri N.
Batra, Shri Shadi Lal
Bhartia, Shrimati Shobhana
Budania, Shri Narendra
Chakraborty, Shri Shyamal
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chatterjee, Shri Prasanta
Chaturvedi, Shri Lalit Kishore
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chavan, Shri Prithviraj
Condpan, Shri Silvius
Daimary, Shri Biswajit
Darda, Shri Vijay Jawaharlal
Das, Shri Kumar Deepak
Dave, Shri Anil Madhav
Deora, Shri Murli
Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao
Dhawan, Shri R.K.
Dhinakaran, Shri T.T.V.
Dhoot, Shri Rajkumar
Dwivedi, Shri Janardan
Elavarasan, Shri A.
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.

Gnanadesikan, Shri B.S.
Govindarajar, Shri N.R.
Gujral, Shri Naresh
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Heptulla, Dr. (Shrimati) Najma A.
Ismail, Shri K.E.
Jaitley, Shri Arun
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Jinnah, Shri A.A.
Jois, Shri M. Rama
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanimozhi, Shrimati
Kannan, Shri P.
Karan Singh, Dr.
Karat, Shrimati Brinda
Katiyar, Shri Vinay
Keishing, Shri Rishang
Kesari, Shri Narayan Singh
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Khuntia, Shri Rama Chandra
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kore, Dr. Prabhakar
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Krishna, Shri S.M.
Kshatriya, Prof. Alka Balram
Kurien, Prof. P.J.
Lad, Shri Anil H.
Lalhming Liana, Shri
Madhu, Shri Penumalli
Mahendra Prasad, Dr.

Maitreya, Dr. V.
Majhi, Shri Bhagirathi
Majitha, Shri Raj Mohinder Singh
Malaisamy, Dr. K.
Malihabadi, Shri Ahmad Saeed
Mangala Kisan, Shri
Mathur, Shri Om Prakash
Mishra, Shri Kalraj
Mohanty, Shri Kishore Kumar
Mohapatra, Shri Pyarimohan
Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh
Moinul Hussan, Shri
Mukut Mithi, Shri
Naidu, Shri M. Venkaiah
Naik, Shri Pravinonandra Rughnathji
Naik, Shri Shantaram Laxman
Nandamuri Harikrishna, Shri
Nandi Yellaiah, Shri
Natarajan, Shrimati Jayanthi
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Nathwani, Shri Parimal
Nayak, Dr. Radhakant
Pany, Shri Rudra Narayan
Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh
Pasha, Shri Syed Azeez
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Kanjibhai
Patel, Shri Surendra Motilal
Pathak, Shri Saman
Pilania, Dr. Gyan Prakash
Pradhan, Shrimati Renubala
Prasad, Shri Ravi Shankar
Punj, Shri Balbir

Rai, Shrimati Kusum
Raja, Shri D.
Rajan, Shri P.R.
Rajeeve, Shri P.
Ram Prakash, Dr.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K. Keshava
Rao, Shri K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rashtrapal, Shri Praveen
Ratanpuri, Shri G.N.
Ratna Bai, Shrimati T.
Raut, Shri Bharatkumar
Raut, Shri Sanjay
Ravi, Shri Vayalar
Rebello, Ms. Mabel
Reddy, Shri G. Sanjeeva
Reddy, Shri M.V. Mysura
Reddy, Dr. N. Janardhana
Reddy, Dr. T. Subbarami
Roy, Shri Abani
Roy, Shri Tarini Kanta
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Rupala, Shri Parshottam Khodabhai
Rupani, Shri Vijaykumar
Sabharwal, Shri Dharam Pal
Sahani, Prof. Anil Kumar
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Sai, Shri Nand Kumar
Sanghi, Shri Gireesh Kumar
Sangma, Shri Thomas
Sarkar, Shri Matilal

Seelam, Shri Jesudasu
Sen, Shri Tapan Kumar
Sengupta, Shri Arjun Kumar
Shafi, Shri Mohammad
Shanappa, Shri K.B.
Shanta Kumar, Shri
Sharma, Shri Raghunandan
Sharma, Shri Satish Kumar
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Shri Arjun
Singh, Shri Ishwar
Singh, Shri Jai Prakash Narayan
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shrimati Maya
Singh, Shri N.K.
Singh, Shri R.C.
Singh, Shri Shivpratap
Singh, Sardar Tarlochan
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Solanki, Shri Kaptan Singh
Soni, Shrimati Ambika
Soz, Prof. Saif-ud-Din
Stanley, Shrimati Vasanthi
Swaminathan, Prof. M.S.
Taimur, Shrimati Syeda Anwara
Tariq Anwar, Shri
Thakor, Shri Natuji Halaji
Thakur, Dr. C.P.
Thakur, Dr. Prabha
Thakur, Shrimati Viplove
Tirya, Ms. Sushila
Tiwari, Shri Sivanand

Trivedi, Shri Y.P.
Uikey, Miss Anusuiya
Vasan, Shri G.K.
Vatsyayan, Dr. (Shrimati) Kapila
Verma, Shri Vikram
Vijayaraghavan, Shri A.
Vora, Shri Motilal
Vyas, Shri Shreegopal
Waghmare, Dr. Janardhan
Yechury, Shri Sitaram
Zhimomi, Shri Khekiho

NOES — NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri M.Veerappa Moily to move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

MR. CHAIRMAN: The question is:

That the Bill, as amended, be passed.

The House divided

MR. CHAIRMAN: Ayes - 186
 Noes - 1

AYES — 186

Abdul Wahab Peevee, Shri
Achuthan, Shri M.P.
Adeeb, Shri Mohammed
Adik, Shri Govindrao Wamanrao
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S.S.
Alvi, Shri Raashid

Amin, Shri Mohammed
Anand Sharma, Shri
Anbalagan, Shri S.
Ansari, Shri Ali Anwar
Antony, Shri A.K.
Apte, Shri Balavant *alias* Bal
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Bagrodia, Shri Santosh
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajaj, Shri Rahul
Bajwa, Shri Varinder Singh
Balaganga, Shri N.
Batra, Shri Shadi Lal
Bhartia, Shrimati Shobhana
Budania, Shri Narendra
Chakraborty, Shri Shyamal
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chatterjee, Shri Prasanta
Chaturvedi, Shri Lalit Kishore
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chavan, Shri Prithviraj
Condpan, Shri Silvius
Daimary, Shri Biswajit
Darda, Shri Vijay Jawaharlal
Das, Shri Kumar Deepak
Dave, Shri Anil Madhav
Deora, Shri Murli
Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao
Dhawan, Shri R.K.
Dhinakaran, Shri T.T.V.
Dhoot, Shri Rajkumar
Dwivedi, Shri Janardan

Elavarasan, Shri A.
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gnanadesikan, Shri B.S.
Govindarajar, Shri N.R.
Gujral, Shri Naresh
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Heptulla, Dr. (Shrimati) Najma A.
Ismail, Shri K.E.
Jaitley, Shri Arun
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Jinnah, Shri A.A.
Jois, Shri M. Rama
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanimozhi, Shrimati
Kannan, Shri P.
Karan Singh, Dr.
Karat, Shrimati Brinda
Katiyar, Shri Vinay
Keishing, Shri Rishang
Kesari, Shri Narayan Singh
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Khuntia, Shri Rama Chandra
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kore, Dr. Prabhakar
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Krishna, Shri S.M.
Kshatriya, Prof. Alka Balram
Kurien, Prof. P.J.
Lad, Shri Anil H.

Lalhming Liana, Shri
Madhu, Shri Penumalli
Mahendra Prasad, Dr.
Maitreya, Dr. V.
Majhi, Shri Bhagirathi
Majitha, Shri Raj Mohinder Singh
Malaisamy, Dr. K.
Malihabadi, Shri Ahmad Saeed
Mangala Kisan, Shri
Mathur, Shri Om Prakash
Mishra, Shri Kalraj
Mohanty, Shri Kishore Kumar
Mohapatra, Shri Pyarimohan
Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh
Moinul Hussan, Shri
Mukut Mithi, Shri
Naidu, Shri M. Venkaiah
Naik, Shri Pravinonandra Rughnathji
Naik, Shri Shantaram Laxman
Nandamuri Harikrishna, Shri
Nandi Yellaiah, Shri
Natarajan, Shrimati Jayanthi
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Nathwani, Shri Parimal
Nayak, Dr. Radhakant
Pany, Shri Rudra Narayan
Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh
Pasha, Shri Syed Azeez
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Kanjibhai
Patel, Shri Surendra Motilal
Pathak, Shri Saman
Pilania, Dr. Gyan Prakash
Pradhan, Shrimati Renubala

Prasad, Shri Ravi Shankar
Punj, Shri Balbir
Rai, Shrimati Kusum
Raja, Shri D.
Rajan, Shri P.R.
Rajeeve, Shri P.
Ram Prakash, Dr.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K. Keshava
Rao, Shri K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rashtrapal, Shri Praveen
Ratanpuri, Shri G.N.
Ratna Bai, Shrimati T.
Raut, Shri Bharatkumar
Raut, Shri Sanjay
Ravi, Shri Vayalar
Rebello, Ms. Mabel
Reddy, Shri G. Sanjeeva
Reddy, Shri M.V. Mysura
Reddy, Dr. N. Janardhana
Reddy, Dr. T. Subbarami
Roy, Shri Abani
Roy, Shri Tarini Kanta
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Rupala, Shri Parshottam Khodabhai
Rupani, Shri Vijaykumar
Sabharwal, Shri Dharam Pal
Sahani, Prof. Anil Kumar
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Sai, Shri Nand Kumar
Sanghi, Shri Gireesh Kumar
Sangma, Shri Thomas

Sarkar, Shri Matilal
Seelam, Shri Jesudasu
Sen, Shri Tapan Kumar
Sengupta, Shri Arjun Kumar
Shafi, Shri Mohammad
Shanappa, Shri K.B.
Shanta Kumar, Shri
Sharma, Shri Raghunandan
Sharma, Shri Satish Kumar
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Shri Arjun
Singh, Shri Ishwar
Singh, Shri Jai Prakash Narayan
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shrimati Maya
Singh, Shri N.K.
Singh, Shri R.C.
Singh, Shri Shivpratap
Singh, Sardar Tarlochan
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Solanki, Shri Kaptan Singh
Soni, Shrimati Ambika
Soz, Prof. Saif-ud-Din
Stanley, Shrimati Vasanthi
Swaminathan, Prof. M.S.
Taimur, Shrimati Syeda Anwara
Tariq Anwar, Shri
Thakor, Shri Natuji Halaji
Thakur, Dr. C.P.
Thakur, Dr. Prabha
Thakur, Shrimati Viplove
Tiriya, Ms. Sushila
Tiwari, Shri Sivanand

Trivedi, Shri Y.P.
Uikey, Miss Anusuiya
Vasan, Shri G.K.
Vatsyayan, Dr. (Shrimati) Kapila
Verma, Shri Vikram
Vijayaraghavan, Shri A.
Vora, Shri Motilal
Vyas, Shri Shreegopal
Waghmare, Dr. Janardhan
Yechury, Shri Sitaram
Zhimomi, Shri Khekiho

NOES — NIL

Shri Sharad Anantrao Joshi

*The motion was carried by a majority of the total membership of the
House and by a majority of not less than two-thirds of the
Members present and voting.*

MR. CHAIRMAN: The Bill, as amended, is passed by the required majority. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow morning.

The House then adjourned at twenty four minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 10th March 2010.